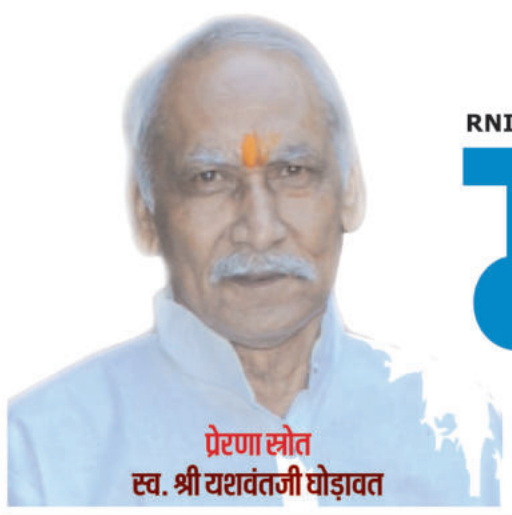

RNI No. MPHIN/2018/76422

बेबाकी के साथ...सच

माही की गूंज

Www.mahikigunj.in, Email-mahikigunj@gmail.com

सुविचार

हर जंग जीत के लिए नहीं लड़ी जाती। कुछ दुनिया को बस यह बातने के लिए लड़ी जाती है कि कोई था रणभूमि में जो लड़ रहा था।

रवीश कुमार

वर्ष-08, अंक - 22 (साप्ताहिक) खवासा, गुरूवार 12 मार्च 2026 पृष्ठ-8, मूल्य -5 रुपए

तेल की आँच में गैस झुलसी

माही की गूंज, झाबुआ डेस्क।

संजय भटेवरा

भारत हमेशा से ही शक्ति प्रिय देश रहा है और ये बुद्ध की धरती है युद्ध की नहीं। लेकिन वर्तमान में तेल पर अधिकार को लेकर छिड़ी जंग में भले ही भारत की कोई भूमिका नहीं है लेकिन इस तेल की आग में भारत में एलपीजी गैस को लेकर संकट पैदा हो गया है। सरकार भले ही वर्तमान में यह दावा कर रही है कि, घरों और परिवहन क्षेत्र को पूरी गैस मिलेगी। लेकिन वर्तमान में बुकिंग का समय 21 दिन से बढ़कर 25 दिन करना और व्यावसायिक सिलेंडरों की आपूर्ति इस बात का संकेत है कि, युद्ध के असर से भारत भी अछूता रहने वाला नहीं है।

पश्चिम एशिया में बढ़ते सैन्य संघर्ष के कारण ऊर्जा आपूर्ति पर पड़े दबाव के बीच केंद्र सरकार ने देश में प्राकृतिक गैस के उपयोग की प्राथमिकताओं को ठप कर दिया है। जिसमें सरकार का कहना है कि, रसोई गैस (एलपीजी) के उत्पादन सीएनजी और पाईप्ड कुकिंग गैस पीएनजी की आपूर्ति को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी। इस संबंध में आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 लागू करते हुए नया आदेश जारी किया गया है। जिसके बाद देश में व्यावसायिक सिलेंडरों की आपूर्ति बाधित होने से रेस्टोरेंट, होटल पर बंद होने का खतरा बढ़ गया है।

सरकार का कहना है कि, गैस की कुल उपलब्धता प्राप्त है लेकिन मौजूदा वैश्विक हालात को देखते हुए घरेलू जरूरतो को सुरक्षित रखना जरूरी है। जिसके बाद देशभर में सिलेंडरों की आपूर्ति को लेकर भय का माहौल है। अफवाहो का दौर भी चल रहा है जिसमें गैस और पेट्रोल- डीजल की कीमते बढ़ने और किल्लत संबंधी चर्चाओं का दौर है। सरकार की तरफ से लगातार दावा किया जा रहा है कि, कोई कमी नहीं है। लेकिन मौजूदा हालातो को देखते हुए आम आदमी चिंतित है। क्योंकि पश्चिमी संघर्ष लंबा खींचने के आसार लग रहे हैं। ऐसे में पेट्रोलियम पदार्थों की आपूर्ति बनाए रखना सरकार के लिए टेढ़ी खीर साबित होगा।

मध्य प्रदेश सरकार ने वर्तमान स्थिति को ध्यान में रखते हुए प्रदेश में पढ़ने वाले प्रभावों की निगरानी और उत्पन्न स्थिति की समीक्षा के लिए मंत्रियों की समिति बनाई है।

तेल संकट के बीच भारत की पहल, ईरान से बातचीत

नई दिल्ली, एजेंसी।

पश्चिम एशिया में जारी सैन्य संघर्ष और ईरान, अमेरिका तथा इजरायल के बीच बढ़ते तनाव के बीच भारत ने कूटनीतिक प्रयास तेज कर दिए हैं। इसी क्रम में भारत के विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर ने ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराघची से दूरभाष पर बातचीत की।

यह वार्ता ऐसे समय में हुई है जब क्षेत्र में तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है और अंतरराष्ट्रीय व्यापारिक मार्गों की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है। ईरानी विदेश मंत्रालय के अनुसार दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया की मौजूदा स्थिति और अंतरराष्ट्रीय व्यापारिक जहाजों की सुरक्षा पर चर्चा की।

अमेरिका और इजरायल द्वारा ईरान पर किए गए सैन्य हमलों के बाद डॉ. जयशंकर और अराघची के बीच यह तीसरी महत्वपूर्ण बातचीत बताई जा रही है। ईरानी पक्ष ने होर्मुज जलडमरूमध्य और फारस की खाड़ी में उत्पन्न असुरक्षित स्थिति के लिए अमेरिका और इजरायल की सैन्य कार्रवाइयों को जिम्मेदार ठहराया है।

डॉ. जयशंकर ने भी कहा कि क्षेत्र की स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है और संपर्क बनाए रखा जाएगा। भारत के लिए यह स्थिति इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि देश अपनी तेल जरूरतों का लगभग 85 प्रतिशत आयात करता है। होर्मुज जलडमरूमध्य से वैश्विक तेल व्यापार का लगभग 20 प्रतिशत गुजरता है, ऐसे में यहां अस्थिरता से तेल और गैस की कीमतों पर असर पड़ सकता है।

इसके अलावा खाड़ी देशों में रह रहे बड़ी संख्या में भारतीय नागरिकों की सुरक्षा भी भारत की प्राथमिकता है। विदेश मंत्री ने जर्मनी और दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्रियों से भी चर्चा कर मौजूदा हालात पर चिंता व्यक्त की।

भारत ने स्पष्ट किया है कि व्यापारिक जहाजों पर हमले स्वीकार्य नहीं हैं और क्षेत्र में शांति बहाल करने के लिए बातचीत तथा कूटनीतिक प्रयास ही सबसे उचित रास्ता हैं।

संवैधानिक पद को राजनीति में न घसीटे

पिछले दिनों पश्चिम बंगाल में देश के महामहिम राष्ट्रपति के दौरे के बाद देश में इस सर्वोच्च पद को लेकर चर्चाओं का दौर जारी है। महामहिम के दौरे पर मुख्यमंत्री या किसी अन्य मंत्री का अगवानी के लिए न पहुंचना तथा बार-बार कार्यक्रम स्थल बदलने को लेकर एक और जहां महामहिम राष्ट्रपति ने सार्वजनिक रूप से नाराजगी व्यक्त की। वही दौरे के बाद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने एक फोटो जारी करते हुए प्रधानमंत्री को आईना दिखाया। जिसमें भारत रत्न सम्मान देने के दौरान प्रधानमंत्री कुर्सी पर बैठे थे और महामहिम राष्ट्रपति खड़ी थी। जिसके बाद देशभर में चर्चाओं का दौर है और देश के प्रधानमंत्री और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री आमने-सामने हो गए हैं। यह सही है कि, मौजूदा राजनीति का स्तर

गिर चुका है लेकिन फिर भी देश के संविधान में संवैधानिक पदों पर बैठे व्यक्तियों के लिए अलग संवैधानिक मर्यादा है जिसका पालन किया जाना चाहिए। इन संवैधानिक पदों पर बैठे व्यक्तियों से भी यह अपेक्षा की जाती है कि, वे इन संवैधानिक पदों को राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का केंद्र न बनाएं। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा व विधानसभा अध्यक्ष एवं राज्यपाल जैसे पदों को राजनीति से दूर ही रहना चाहिए। यही नहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री, मुख्य चुनाव आयोग पर भी आरोप लगाती रही। राजनीतिक मजबूरी अपनी जगह है लेकिन संवैधानिक पदों पर बैठे व्यक्तियों के लिए निर्धारित प्रोटोकॉल का पालन किया जाना अनिवार्य है।

इच्छामृत्यु की अनुमति, फैसला सुनाते समय भावुक हुए न्यायाधीश

नई दिल्ली, एजेंसी।

सर्वोच्च न्यायालय ने बुधवार को 32 वर्षीय हरीश राणा को इच्छामृत्यु की अनुमति दे दी। फैसला सुनाते समय अदालत का माहौल भावुक हो गया और न्यायमूर्ति जे. बी. पारदीवाला की आंखें नम हो गईं। न्यायमूर्ति पारदीवाला और न्यायमूर्ति के. वी. विश्वनाथन की पीठ ने हरीश राणा के माता-पिता को उनका वेंटिलेटर हटाने की अनुमति प्रदान की है। हरीश राणा पिछले 13 वर्षों से कोमा की स्थिति में हैं।

इस मामले ने देशभर में सम्मानजनक मृत्यु के अधिकार से जुड़ी चर्चा को भी जन्म दिया था। निर्णय सुनाते समय न्यायमूर्ति पारदीवाला ने कहा कि, हरीश राणा कभी एक होनहार छात्र थे और पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन एक दुर्घटना ने उनके जीवन की दिशा बदल दी। मामले की परिस्थितियों का उल्लेख करते हुए वे कुछ क्षणों के लिए भावुक भी हो गए।

न्यायालय ने अपने निर्णय में कहा कि ऐसे मामलों में यह नहीं देखा जाता कि मरीज के लिए मृत्यु बेहतर है या नहीं, बल्कि यह महत्वपूर्ण होता है कि जीवन को बनाए रखने वाला उपचार मरीज के हित में है या नहीं। अदालत के अनुसार हरीश राणा केवल सोने और जागने की अवस्था में रहते हैं, लेकिन किसी प्रकार की सार्थक प्रतिक्रिया देने में असमर्थ हैं और अपने सभी दैनिक कार्यों के लिए पूरी तरह दूसरों पर निर्भर हैं।

अदालत ने बताया कि, हरीश को एक विशेष नली के माध्यम से चिकित्सकीय पोषण दिया जा रहा है और इतने वर्षों में उनकी स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ है। हरीश राणा वर्ष 2013 में अपनी इमारत की चौथी मंजिल से गिर गए थे, जिससे उनके सिर में गंभीर चोट लगी तब से कोमा में हैं।

सर्वोच्च न्यायालय ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली के चिकित्सकों की रिपोर्ट का भी अवलोकन किया, जिसमें बताया गया था कि, मरीज के स्वस्थ होने की संभावना नहीं है। इसके बाद अदालत ने निर्देश दिया कि उपचार को सम्मानजनक तरीके से चरणबद्ध रूप से बंद किया जाए, ताकि मरीज की गरिमा बनी रहे।

रिचार्ज खत्म होने पर इनकमिंग बंद करना मनमानी- श्री चड्ढा

नई दिल्ली, एजेंसी।

आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने संसद के उच्च सदन में मोबाइल उपभोक्ताओं से जुड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि प्रीपेड मोबाइल रिचार्ज समाप्त होने पर इनकमिंग कॉल और संदेश सेवा बंद कर देना मोबाइल कंपनियों की मनमानी है, जिससे करोड़ों उपभोक्ता प्रभावित होते हैं।

राघव चड्ढा ने कहा कि दूरसंचार नियामक प्राधिकरण के आंकड़ों के अनुसार देश में करीब 125 करोड़ मोबाइल उपभोक्ता हैं, जिनमें लगभग 90 प्रतिशत प्रीपेड उपभोक्ता हैं। उन्होंने बताया कि प्रीपेड उपभोक्ताओं को रिचार्ज की वैधता खत्म होने के बाद इनकमिंग कॉल और संदेश बंद होने की समस्या का सामना करना पड़ता है।

उन्होंने कहा कि मोबाइल नंबर आज केवल बातचीत का माध्यम नहीं रहा, बल्कि यह व्यक्ति की डिजिटल पहचान बन चुका है। बैंकिंग सेवाएं, यूपीआई भुगतान, रेल टिकट बुकिंग, पैन-आधार सत्यापन, नौकरी से जुड़े कॉल, अस्पतालों की जानकारी और पारिवारिक संपर्क जैसे कई जरूरी कार्य मोबाइल पर आने वाले कॉल और संदेशों के माध्यम से ही होते हैं। ऐसे में रिचार्ज न होने पर इनकमिंग सेवा बंद कर देना उपभोक्ताओं के लिए परेशानी का कारण बनता है।

राघव चड्ढा ने सरकार और दूरसंचार नियामक से मांग की कि प्रीपेड मोबाइल कनेक्शन में इनकमिंग कॉल और संदेश की सुविधा अंतिम रिचार्ज की तारीख से कम से कम एक वर्ष तक जारी रहनी चाहिए। साथ ही किसी भी मोबाइल नंबर को तीन वर्ष से पहले निष्क्रिय नहीं किया जाना चाहिए और उपभोक्ताओं के लिए कम कीमत वाले विशेष रिचार्ज विकल्प उपलब्ध कराए जाने चाहिए।

राहुल का आरोप: विपक्ष के नेता को बोलने से रोका गया

नई दिल्ली।

लोकसभा में अध्यक्ष ओम बिरला को पद से हटाने के प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान सत्तापक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस देखने को मिली। इस दौरान कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि उन्हें सदन में बोलने का अवसर नहीं दिया गया।

राहुल गांधी ने कहा कि सदन में जब भी विपक्ष अपनी बात रखने के लिए खड़ा होता है, उसे रोका-टोका जाता है। उन्होंने कहा कि यह चर्चा लोकतंत्र और अध्यक्ष की भूमिका से जुड़ी है, लेकिन कई बार उनका नाम लेकर टिप्पणी की गई और फिर भी उन्हें अपनी बात रखने का पूरा अवसर नहीं मिला। उन्होंने कहा कि यह सदन पूरे देश का प्रतिनिधित्व करता है और पहली बार ऐसा हो रहा है जब विपक्ष के नेता को बोलने नहीं दिया जा रहा है।

राहुल गांधी के बयान पर भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद ने आपत्ति जताते हुए कहा कि ऐसा कभी नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत किसी भी प्रकार का समझौता नहीं करेगा। प्रसाद ने कहा कि संसदीय परंपराओं में इस तरह के विरोध पहले भी होते रहे हैं।

रविशंकर प्रसाद ने उदाहरण देते हुए कहा कि संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार के दौरान भी ऐसी स्थिति सामने आई थी, जब तत्कालीन विपक्ष के नेता लालकृष्ण आडवाणी को

लोकसभा अध्यक्ष सोमनाथ चटर्जी ने बोलने की अनुमति नहीं दी थी। उस समय भाजपा ने इसका विरोध करते हुए सदन से बहिर्गमन किया था।

उधर राज्यसभा सदस्य कपिल सिब्बल ने रसोई गैस की कमी के मुद्दे पर कहा कि ऐसी स्थिति में घरेलू उपभोक्ताओं को प्राथमिकता देना सरकार का अधिकार है। उन्होंने कहा कि यदि युद्ध की स्थिति लंबे समय तक बनी रहती है तो कई क्षेत्रों पर इसका असर पड़ सकता है।

पीएम का राहुल पर तंज: छोटी सोच वाले को देश का विकास नही दिखेगा

कोच्चि।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को केरल दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने कोच्चि में लगभग 10 हजार 800 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इसके बाद उन्होंने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की एक जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर बिना नाम लिए तंज कसा।

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कांग्रेस के युवराज को यह भी जानकारी नहीं है कि आज भारत के युवा ड्रोन निर्माण के क्षेत्र में नई उपलब्धियां हासिल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि केरल के

युवाओं ने भी ड्रोन तकनीक को लेकर कई नवाचार और नए उद्यम शुरू किए हैं। जो व्यक्ति छोटे दायरे और सीमित सोच में सिमटा हो, उसे देश का विकास दिखाई नहीं देता।

इससे पहले प्रधानमंत्री अखिल केरल धीवर सभा के स्वर्ण जयंती समारोह में भी शामिल हुए। यहां उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने केरल का नाम बदलकर 'केरलम' करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। यह मलयाली समाज के लिए खुशी का क्षण है।

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि केरलम के पास प्रकृति, संस्कृति, प्रतिभा, तकनीक और समुद्र जैसे अनेक संसाधनों का आशीर्वाद है, लेकिन इसके बावजूद यहां विकास की गति उतनी तेज नहीं रही, जितनी होनी चाहिए थी। उन्होंने कहा कि वाम लोकतांत्रिक मोर्चा और संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा की सरकारों ने विकास के लिए अपेक्षित प्रयास नहीं किए।

उन्होंने जनता से आह्वान करते हुए कहा कि कांग्रेस और वामपंथी दलों को 70 वर्ष से अधिक समय दिया जा चुका है। अब भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को सेवा का अवसर दिया जाना चाहिए, जिससे केरलम के विकास को नई गति मिल सके।

प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित केरलम के लिए पर्यटन, प्रतिभा और तकनीक को नए अवसर देना आवश्यक है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस और वामपंथी दल आत्मनिर्भर भारत अभियान का मजाक उड़ाते रहे हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं।

प्रधानमंत्री मोदी ने मछुआरा समुदाय का उल्लेख करते हुए कहा कि समुद्री अर्थव्यवस्था केवल पारंपरिक मछली पकड़ने तक सीमित नहीं है। मत्स्य पालन के क्षेत्र में भी नए अवसर सामने आ रहे हैं। केरल में आई विनाशकारी बाढ़ के दौरान मछुआरों ने साहस और सेवा का परिचय देते हुए कई लोगों की जान बचाई थी, जिसे पूरा देश सम्मान के साथ याद करता है।

उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने मत्स्य पालन क्षेत्र के विकास के लिए अलग मंत्रालय का गठन किया है और प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत केरल के लिए लगभग 1400 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। साथ ही समुद्र में जाने वाले मछुआरों की सुरक्षा के लिए उपग्रह तकनीक का भी उपयोग किया जा रहा है। राष्ट्रीय मत्स्य डिजिटल मंच के माध्यम से मछुआरे, व्यापारी और निर्यातक एक ही स्थान पर पंजीकरण कर योजनाओं का लाभ ले सकते हैं।

जल संसाधन विभाग पर बरसे पटवारी, टेंडर सिंडिकेट और फर्जी बैंक गारंटी की जांच की मांग

भोपाल।

मध्यप्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जितेंद्र (जीतू) पटवारी ने जल संसाधन विभाग की टेंडर व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए गंभीर अनियमितताओं के आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि यह केवल कागजी प्रक्रिया का मामला नहीं है, बल्कि इसका असर उन सिंचाई परियोजनाओं पर पड़ रहा है जिनका इंतजार किसान लंबे समय से कर रहे हैं।

पटवारी ने आरोप लगाया कि विभाग के कई बड़े टेंडरों में बार-बार वही सीमित कंपनियां दिखाई देती हैं। कभी वे पहली, दूसरी या तीसरी सबसे कम बोली लगाने वाली स्थिति में रहती हैं। उन्होंने कहा कि यदि प्रतिस्पर्धा पूरी तरह खुली है तो टेंडर प्रक्रिया में बार-बार वही नाम क्यों सामने आते हैं। उनके अनुसार यह सामान्य प्रतिस्पर्धा नहीं बल्कि तयशुदा क्रम जैसा दिखाई देता है।

उन्होंने कहा कि जब बोली प्रक्रिया में भाग लेने वाली कंपनियों का दायरा सीमित दिखे और परिणाम बार-बार एक ही समूह के आसपास घूमते दिखाई दें, तो विभाग को सार्वजनिक रूप से यह स्पष्ट करना चाहिए कि पात्रता, तकनीकी मूल्यांकन और वित्तीय मूल्यांकन किस आधार पर तय किया गया।

पटवारी ने कुछ सिंचाई परियोजनाओं का उल्लेख करते हुए तकनीकी स्तर पर भी अनियमितताओं का आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया कि कई स्थानों पर जमीन पर उच्च घनत्व वाले प्लास्टिक पाइप लगाए गए, जबकि भुगतान ढलवा लोहे के पाइप के नाम पर किया गया। यदि यह आरोप सही साबित होता है तो यह केवल गुणवत्ता का नहीं बल्कि वित्तीय अनियमितता का भी मामला होगा, क्योंकि दोनों सामग्रियों की लागत और टिकाऊपन अलग-अलग होती है।

उन्होंने कहा कि पाइप जैसी मूलभूत सामग्री में बदलाव का असर अंततः किसानों पर पड़ता है। योजना कागजों में पूरी दिखती है और भुगतान हो जाता है, लेकिन पाइपलाइन की क्षमता और आयु पर सवाल खड़े हो जाते हैं, जिससे सिंचाई व्यवस्था प्रभावित होती है।

कांग्रेस अध्यक्ष ने यह भी आरोप लगाया कि जल संसाधन विभाग में पिछले लगभग डेढ़ वर्ष से बड़े टेंडर जारी नहीं किए गए हैं, जबकि कई सिंचाई परियोजनाएं लंबित पड़ी हैं। उनका कहना है कि परियोजनाएं समय पर आगे नहीं बढ़ेंगी तो नहरों और पाइपलाइन नेटवर्क का विस्तार भी रुक जाएगा और इसका सीधा असर किसानों पर पड़ेगा।

पटवारी ने बैंक गारंटी के मुद्दे को उठाते हुए कहा कि जल निगम में फर्जी बैंक गारंटी का मामला सामने आने के बाद 9 दिसंबर 2024 को इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी लागू करने का आदेश जारी किया गया था, लेकिन जल संसाधन विभाग और नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण में यह व्यवस्था अब तक लागू नहीं की गई है।

कांग्रेस ने मांग की है कि जल संसाधन विभाग में जमा सभी बैंक गारंटियों की जांच कराई जाए, इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी व्यवस्था तत्काल लागू की जाए और वर्ष 2023-24 में जारी किए गए टेंडरों की न्यायिक जांच कराई जाए।

माता जी को बासी व्यंजनों का भोग

माही की गूंज, आम्बुआ।

होलिका दहन के बाद लगभग एक सप्ताह तक चलने वाले हिन्दू सनातन धर्म के विभिन्न आयोजनों में अंतिम आयोजन शीतला सप्तमी का पर्व 10 मार्च को धूमधाम से मनाया गया।

हिन्दू सनातन धर्म में होलिका दहन के बाद मनाए जाने वाले पर्वों में शीतला सप्तमी का विशेष महत्व रखती है। इस दिन शीतला माता को एक दिन पुर्व बनाया गया भोजन यानि कि बासी भोजन जिसे कुछ स्थानों पर वसोडा भी कहा जाता है का भोग लगाया जाता है। जिसके बाद इसी बासी भोजन को परिवार सहित ईष्ट मित्रों आदि को भी खाया और खिलाया जाता है। इस दिन घरों में चूल्हा नहीं जलता है। मंगलवार को आम्बुआ,बोरझाड सहित ग्रामीण क्षेत्रों से अनेक भक्तों ने रात 12 बजे के बाद से शीतला माता मंदिर में आना प्रारंभ किया जोकि दोपहर तक ऐसा ही सिलसिला चलता रहा। यह पर्व विशेष कर महिलाओं का रहता है इसलिए महिलाओं की अधिक भीड़ उमड़ी। आम्बुआ में शीतलता माता मंदिर क़स्बे से बाहर समधनी फलिया के समीप है, दूर होने के बाबजूद पूजा अर्चना करने वाले रात्रि 11 बजे से मंदिर पहुंचने लगे थे, लेकिन वहां की व्यवस्था संभालने वाले प्रजापति समाज के कार्य कर्ताओं ने 12 बजे बाद जब सप्तमी तिथि प्रारंभ हुई तब मंदिर का दरवाजा खोला और व्यवस्थित तरीके से पंक्ति में खड़े हो कर अपनी बारी के मान से शालीनता के साथ माता जी की पूजा अर्चना कर परिवार में सुख-शांति बनी रहे की प्रार्थना की। स्मरण रहे कि, आम्बुआ में स्थित शीतला माता मंदिर ऐसा मंदिर है जहां आम्बुआ के अतिरिक्त समीप ग्राम बोरझाड के भक्त भी पूजा करने हेतु आते हैं। दोनों ग्रामों के प्रजापति समाज के कार्यकर्ता इस अवसर पर व्यवस्था सम्हालते हैं जिसमें टेंट, कुर्सी,दरी तथा शीतल जल एवं विद्युत व्यवस्था प्रमुख रहती है।

एचपीवी टीका: बच्चियों की तबीयत बिगड़ी

माही की गूंज, ग्वालियर।

प्रदेश में चल रहे एचपीवी टीकाकरण अभियान के बीच ग्वालियर जिले से एक मामला सामने आया है, जहां टीका लगने के बाद कई बच्चियों की तबीयत बिगड़ गई। परिजनों की शिकायत के बाद बच्चियों को सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया। चिकित्सकों के अनुसार सभी बच्चियों की हालत फिलहाल सामान्य बताई जा रही है।

जानकारी के अनुसार ग्वालियर जिले के पिछोर कस्बे के बारकरी जिगनिया गांव की कुछ बच्चियों को टीका लगाए जाने के बाद बुखार, उल्टी, पेट दर्द और चक्कर आने की शिकायत हुई। इसके बाद परिजन घबरा गए और बच्चियों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। अस्पताल में उनका उपचार किया गया और अब उनकी स्थिति स्थिर बताई जा रही है।

इस मामले में परिजनों ने आरोप लगाया है कि, आंगनबाड़ी और आशा कार्यकर्ता गांव में आई थीं और उन्होंने बच्चियों के प्रपत्र भरवाने की बात कही। परिजनों का कहना है कि, उन्हें बताया गया था कि इससे बच्चियों की शादी के समय 50 हजार रुपए की सहायता मिलेगी। इसी बहाने बच्चियों को ले जाकर टीका लगा दिया गया। परिजनों ने मीडिया को कहा कि, यदि बच्चियों को कोई गंभीर परेशानी हो जाती तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेता। बताया जा रहा है कि कुल नौ बच्चियों को अस्पताल में भर्ती कराया गया था।

उल्लेखनीय है कि बच्चियों को सर्वाइकल कैंसर से बचाने के लिए यह राष्ट्रीय टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। मध्य प्रदेश में 14 से 15 वर्ष आयु वर्ग की लगभग 8 लाख बच्चियों को यह टीका लगाने का लक्ष्य रखा गया है। इस टीके की बाजार में कीमत चार हजार रुपए से अधिक बताई जाती है, लेकिन सरकार इसे निःशुल्क उपलब्ध करा रही है।

बाजार में सन्नाटा: कृषक खेती कार्य में जुटे

बाजार में सन्नाटा पसरा।

गेहूं की फसल की कटाई करते हुए कृषक।

माही की गूंज, आम्बुआ।

इस समय मौसम में हर रोज कुछ न कुछ बदलाव देखा और मेहसूस किया जा रहा है। कभी हल्की ठंड तो दिन में तेज धूप के कारण गर्मी मेहसूस की जा रही है। बदलते मौसम के कारण बीमारियों में भी इजाफा हो रहा है, अस्पतालों में बीमारों की भीड़ देखी जा सकती है।

मार्च के महीने में होलिका दहन किया जाने के बाद से ही क्षेत्र में गर्मी मेहसूस की जाने लगी है, ठंड का मौसम अचानक विदा हो गया और शाल - स्वेटर आदि गर्म कपड़े छूट चुके हैं। क्षेत्र में रात का तापमान जहां 18-20 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह रहा है वहीं दिन के तापमान में वृद्धि होती जा रही है, आज 9 मार्च को दोपहर के समय 36--38 डिग्री सेल्सियस दर्ज की गई। क्षेत्र में अनेक जगहों पर ठंडाई तथा ठंडे पेय पदार्थों की दुकानें सजाई जा चुकी हैं जिनमें मानक अमानक सभी तरह के पेय तथा खाद्य सामग्रियों का विक्रय धड़ल्ले से हो रहा है,इन मौसमी दुकानों पर कितने मौसमी फलों का उपयोग हो रहा है यह जांच का विषय हो सकता है।

क्षेत्र में बिगड़ते मौसम से चिंतित ग्रामीण कृषक खेतों में पक कर खड़ी चना राई, तथा गेहूं आदि की कटाई में जुटे हुए हैं जिस कारण बाजारों में सन्नाटा पसरा हुआ है और शहरी व्यापारी हाथ पर हाथ धरे बैठे हुए हैं। उन्हें ग्राहकों के आने का इंतजार करना पड़ रहा है,जो ग्रामीण होली पर्व पर घर आए थे वे भी वापस लौटने लगे हैं अब ये लोग शादी विवाह के समय या फिर वर्षा ऋतु प्रारंभ होने के करीब वापस गांव लौटेंगे तथा गांव की खेतों में बुआई कर पुनः गुजरात मजदूरी करने चले जाएंगे।

खनन कारोबारी के यहां आयकर की छापेमारी

भोपाल।

राजधानी भोपाल में बुधवार को आयकर विभाग की टीम ने खनन कारोबारी दिलीप गुप्ता के ठिकानों पर छापेमारी की कार्रवाई की। बताया जा रहा है कि दिल्ली से आई आयकर विभाग की टीम ने भोपाल सहित कई शहरों में एक साथ यह कार्रवाई की। कारोबारी पर स्वीकृति से अधिक खनन करने और प्रभावशाली व्यक्ति को रिश्वत देने के आरोप लगाए गए हैं।

सूत्रों के अनुसार आयकर विभाग को शिकायत मिली थी कि दिलीप गुप्ता ने निर्धारित सीमा से अधिक खनन किया और इसके लिए खनन से जुड़े मामलों में मदद लेने के बदले करीब पांच करोड़ रुपये की रिश्वत दी गई। इसी शिकायत के आधार पर विभाग ने छापेमारी की कार्रवाई शुरू की।

आयकर विभाग की टीम ने भोपाल के अलावा दिल्ली, छतरपुर और कानपुर सहित अन्य स्थानों पर भी एक साथ कार्रवाई की है। सभी स्थानों पर सुरक्षा के लिए पुलिस बल तैनात किया गया है। बताया जा रहा है कि जांच के दौरान कुछ व्हाट्सएप संदेश भी टीम के हाथ लगे हैं, जिनके आधार पर कई दस्तावेजों की जांच की जा रही है।

प्रारंभिक जांच में होशंगाबाद रोड स्थित एक आलीशान आवासीय टाउनशिप में साझेदारी से जुड़े दस्तावेज भी मिलने की जानकारी सामने आई है। जांच में मध्य प्रदेश पुलिस और प्रशासन के कुछ अधिकारियों की भी सहायता ली जा रही है। माना जा रहा है कि मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रवर्तन निदेशालय भी जांच में शामिल हो सकता है।

उल्लेखनीय है कि पिछले वर्ष नवंबर में आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो ने भी दिलीप गुप्ता के भोपाल स्थित ठिकानों पर छापा मारा था। उस समय चुनाभट्टी स्थित आवास और एमपी नगर स्थित कार्यालय में कार्रवाई के दौरान 21 लाख रुपये से अधिक नकद राशि और 60 से अधिक जमीनों से जुड़े पंजीकृत दस्तावेज तथा समझौते जब्त किए गए थे। साथ ही 50 से अधिक कंपनियों से संबंधित अभिलेख भी मिले थे, जिनमें लेन-देन, हिस्सेदारी और निवेश से जुड़ी जानकारी शामिल थी।

दस दिन के युद्ध से गैस आपुर्ति घटी, बड़े संकट से कैसे निपटेगी सरकार-कमलनाथ

भोपाल।

मध्यप्रदेश में रसोई गैस की आपूर्ति में कमी को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने राज्य सरकार पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि दो देशों के बीच कुछ दिनों तक चले युद्ध का असर अब प्रदेश के घरों की रसोई तक पहुंचने लगा है। उन्होंने कहा कि यदि अभी से स्थिति को गंभीरता से नहीं लिया गया तो भविष्य में बड़ा संकट जनता के लिए और कठिनाइयाँ पैदा कर सकता है।

कमलनाथ ने समाचार माध्यमों में प्रकाशित खबरों का हवाला देते हुए कहा कि प्रदेश में रसोई गैस की आपूर्ति लगभग 30 प्रतिशत तक घट गई है। हालात ऐसे हैं कि सरकार को उद्योगों और अन्य उपभोक्ताओं के लिए गैस आपूर्ति सीमित करने जैसे कदम उठाने पड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह केवल आपूर्ति का संकट नहीं बल्कि आपदा प्रबंधन की तैयारी में कमी का संकेत भी है।

पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि यदि दुनिया के किसी अन्य हिस्से में हुई सीमित अवधि की लड़ाई का असर सीधे मध्यप्रदेश की रसोई तक पहुंच सकता है, तो इससे सरकार की तैयारियों पर गंभीर प्रश्न खड़े होते हैं। उन्होंने पूछा कि क्या सरकार के पास ऐसी कोई दीर्घकालिक योजना नहीं है, जिससे संकट की स्थिति में भी जनता को आवश्यक वस्तुओं की कमी का सामना न करना पड़े।

कमलनाथ ने कहा कि आज रसोई गैस आम नागरिक के जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुकी है। गरीब परिवारों से लेकर मध्यम वर्ग तक लगभग हर घर इसकी जरूरत पर निर्भर है। ऐसे में यदि आपूर्ति में 30 प्रतिशत तक कमी आती है तो यह केवल प्रशासनिक चुनौती नहीं बल्कि नीतिगत कमजोरी का संकेत भी माना जा सकता है।

उन्होंने कहा कि सरकार अक्सर अपनी उपलब्धियों के बड़े दावे करती है, लेकिन संकट की स्थिति में व्यवस्थाओं की वास्तविकता सामने आ जाती है। यदि कुछ दिनों की अंतरराष्ट्रीय स्थिति से ही प्रदेश की गैस व्यवस्था प्रभावित हो जाती है, तो किसी बड़े वैश्विक संकट में हालात और गंभीर हो सकते हैं।

कमलनाथ ने राज्य सरकार से आग्रह किया कि इस स्थिति से सबक लेते हुए आवश्यक वस्तुओं के लिए मजबूत भंडारण व्यवस्था, वैकल्पिक आपूर्ति प्रणाली और प्रभावी आपातकालीन प्रबंधन योजना तैयार की जाए, ताकि भविष्य में जनता को ऐसी परेशानी का सामना न करना पड़े। उन्होंने कहा कि किसी भी सरकार की वास्तविक क्षमता का आकलन संकट के समय ही होता है, इसलिए सरकार को दूरदर्शी नीतियों के साथ जनता का भरोसा बनाए रखना चाहिए।

जांच के आदेश: फीस जमा होने के बाद भी छात्र-छात्राओं को परीक्षा से रोका

माही की गूंज, उमरिया।

विकटगंज की निजी परफेक्ट पब्लिक स्कूल में 112 छात्र-छात्राओं को वार्षिक परीक्षा में बैठने से रोकने का मामला सामने आया है। इस घटना के बाद अभिभावकों में नाराजगी है। अभिभावकों का कहना है कि उन्होंने विद्यालय की फीस जमा कर दी थी, इसके बावजूद बच्चों को परीक्षा देने की अनुमति नहीं दी गई।

जानकारी के अनुसार परीक्षा से रोके जाने के बाद छात्र-छात्राओं और उनके अभिभावकों ने विद्यालय प्रबंधन के खिलाफ नाराजगी जताई। उनका कहना है कि, अचानक लिए गए इस फैसले से बच्चों का भविष्य प्रभावित हो सकता है। वहीं परफेक्ट पब्लिक स्कूल की संचालक सत्येंद्र यादव ने भी स्वीकार किया है कि, लगभग 112 छात्र-छात्राओं को परीक्षा में बैठने से वंचित किया गया है।

मामले को गंभीरता से लेते हुए शिक्षा विभाग ने भी संज्ञान लिया है। जिला परियोजना समन्वयक केके डहेलिया ने कहा है कि, यदि जांच में यह साबित होता है कि विद्यालय प्रबंधन ने नियमों के विरुद्ध छात्रों को परीक्षा से रोका है, तो संबंधित संचालक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

शीतला सप्तमी के दो दिवसीय मेले में दिखी भगोरिया की झलक

जनपद अध्यक्ष और पूर्व विधायक मांदल की थाप पर झूमे

माही की गूंज,पेटलावद।

ग्राम पंचायत करडावद द्वारा मंगलवार को शीतला सप्तमी पर आयोजित दो दिवसीय मेले के पहले दिन ही काफी भीड़ आई। आसपास के करीब 50 से अधिक गांव के ढोल-मादल के साथ लोग आए और जमकर नाच-गाना किया और खरीदारी की। इस मौके पर बीजेपी एवं कांग्रेस ने गैर भी निकाली जिससे मिनी भगोरिया की झलक दिखाई दी। ग्रामीणों ने इसके बाद झूले-चकरी का भी आनंद उठाया। शीतला सप्तमी का यह पारंपरिक मेला क्षेत्र में काफी लोकप्रिय है। भगोरिया पर्व के बाद इस मेले को लेकर क्षेत्र में काफी उत्सुकता बनी रहती है।

इसके पूर्व मेले की विधिवत शुरुआत जनपद अध्यक्ष रमेश सोलंकी एवं मंडल अध्यक्ष संजय कहार ने फीता काटकर की। इस अवसर पर ग्राम पंचायत सरपंच रामसिंग सिंगाड़ सहित बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधिगण मौजूद थे।

जमकर थिरके पूर्व विधायक

मेले में कांग्रेस ने भी गैर निकाली जिसमें पूर्व विधायक वालसिंह मैंड़ा, ब्लॉक कांग्रेस उपाध्यक्ष भरत मुलेवा, जावेद लोधी के साथ स्थानीय नेताओ ने ढ़ोल-मांदल के साथ जमकर नाच-गाना किया। मेले में कई स्थानों पर शुद्ध जल की व्यवस्था की गई थी। वहीं मेले में सुरक्षा की दृष्टि को मद्देनजर रखते हुए तहसीलदार अनिल बघेल, थाना प्रभारी निर्भय सिंह भूरिया, सारंगी चौकी प्रभारी दीपक देवरे मय दल-बल के साथ मौजूद थे। मेले में मुख्य आकर्षण झूला-चकरी के साथ बर्फ के गोले, फोटो की दुकान, हाथों पर नाम गुदवाना, श्रंगार सामग्री की खरीदी की रही। युवाओं में भी विशेष रुप से ड्रेस कोड के साथ चश्मे को लेकर काफी उत्साह देखा गया। वही लड़कियां भी समूह के साथ एक जैसी ड्रेस कोड में दिखी। उल्लेखनीय है कि, करडावद का यह मेला शीतला सप्तमी के दिन मनाने की पुरानी परंपरा है और वर्षों से यह परंपरा आज तक कायम है।

प्रेरणादायक पहलः पीपाड़ा की मृत्यु उपरांत हुआ नेत्रदान

माही की गूंज, सारंगी। संजय उपाध्याय

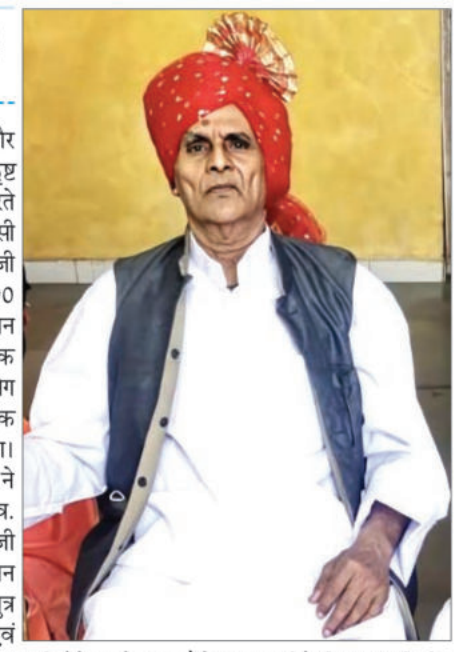

मानवता और सेवा का उत्कृष्ट उदाहरण पेश करते हुए सारंगी निवासी स्व. शांतिलाल जी पीपाड़ा (आयु 90 वर्ष) का नेत्रदान तेरापंथ युवक परिषद के सहयोग से सफलता पूर्वक संपन्न कराया गया।

परिजनों ने बताया कि, स्व. शांतिलाल जी पीपाड़ा के निधन के बाद उनके पुत्र राजेंद्र, राकेश एवं अभय पीपाड़ा ने सहमति देते हुए नेत्रदान जैसे पुण्य कार्य के लिए तुरंत निर्णय लिया। परिवार के इस प्रेरणादायक कदम से दो नेत्रहीन व्यक्तियों के जीवन में नई रोशनी पहुंचेगी और उन्हें दुनिया देखने का अवसर मिलेगा। नेत्रदान की पूरी प्रक्रिया दाहोद के दृष्टि नेत्रालय के माध्यम से विधिवत रूप से सम्पन्न की गई। तेरापंथ युवक परिषद के सदस्यों ने भी इस कार्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए परिवार के इस निर्णय की सराहना की और समाज को भी नेत्रदान के लिए आगे आने का संदेश दिया।

स्व. शांतिलाल पीपाड़ा के परिवार द्वारा लिया गया यह निर्णय समाज के लिए एक मिसाल है, जो यह दर्शाता है कि, मृत्यु के बाद भी किसी के जीवन में उजाला किया जा सकता है।

श्री जिनेंद्र मुनि जी का जन्म दिवस हर्षोल्लास से मनाया

माही की गूंज ,पेटलावद।

आचार्य श्री उमेश मुनि जी महाराज साहब के बुद्ध पुत्र और धर्मदासगण के गणनायक प्रवर्तक श्री जिनेंद्र मुनि जी महाराज साहब का 67वां जन्म दिवस शीतला सप्तमी के पावन अवसर पर पेटलावद श्री संघ द्वारा उत्साह के साथ मनाया गया।

उक्त मांगलिक अवसर पर स्थानीय श्री संघ ने विभिन्न धार्मिक अनुष्ठानों और सेवा कार्यों के माध्यम से अपनी मंगल भावनाएं प्रदर्शित की। कार्यक्रम के दौरान श्रावक-श्राविकाओं ने दो-दो सामायिक अणु, जिनेंद्र चालीसा का पाठ और नवकार मंत्र के सामूहिक जाप के साथ महाराज साहब के गुणों का भावपूर्ण बखान किया। आयोजन के दौरान संघ सचिव पारसमल सोलंकी ने महाराज साहब के संदेशों को रेखांकित करते हुए कहा कि, प्रवर्तक श्री हमेशा हमें अशुभ चिंतन का त्याग कर शुभ चिंतन में रमण करने की प्रेरणा देते हैं। उन्होंने धर्म और शुक्ल ध्यान को अपनाने तथा जीवन से आर्त व रौद्र ध्यान के है को ही श्रेष्ठ जीवन का आधार बताया।

संघ संवाददाता जितेंद्र मेहता ने महाराज साहब के व्यक्तित्व को भगवान महावीर की साधु परिभाषा का जीवंत रूप बताया। जबकि स्वाध्यायी सोहनलाल चाणोदीया ने वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों में उनके जैसे संतों की प्रासंगिकता पर जोर दिया। इस कड़ी में रोहित कटकानी और चेतन कटकानी ने अपने विचारों से, जबकि रवि मेहता, खुशबू कटकानी, वंदना सोलंकी, रिंकू और पूजा सोलंकी ने सुमधुर स्तवन के माध्यम से अपनी भावनाएं व्यक्त कीं। कवि पदम मेहता ने काव्य पाठ कर महाराज साहब के प्रति मंगल कामनाएं प्रेषित कीं। कार्यक्रम का सफल संचालन राजेंद्र कटकानी ने किया और वरिष्ठ श्रावक हस्तीमल बाफना द्वारा सुनाए गए मंगल पाठ के साथ धार्मिक सभा का समापन हुआ।

इस गरिमामयी उपस्थिति में संघ अध्यक्ष अशोक मेहता, उपाध्यक्ष कांतिलाल झाड़मता, कोषाध्यक्ष संजय भंडारी और बहू मंडल अध्यक्षा श्रीमती संगीता मेहता सहित बड़ी संख्या में समाजजन मौजूद रहे। भक्ति भाव का यह क्रम केवल स्थानक तक सीमित नहीं रहा, दोपहर में संघ अध्यक्ष और पदाधिकारियों ने गौशाला पहुंचकर गौ सेवा की और महाराज साहब के दीर्घायु होने की कामना की।

रथ में सवार होकर मां ने किया भ्रमण

माही की गूंज, रायपुरिया/झकनावदा।

झकनावदा में शीतला सप्तमी के एक दिन पूर्व प्रतिवर्ष के अनुसार इस वर्ष भी मंगलवार को समस्त प्रजापति समाज के द्वारा अपनी आराध्य देवी, प्रकृति जीव दयालु मां श्री श्रीयादे मां (शीतला माता) के मंदिर को सु-सज्जित कर फूलों से आकर्षित सजावट की गई। तथा श्री श्रीयादें मां (शीतला माता) को रथ में सवार कर बैंड बाजों के साथ उत्साह व उमंग से नृत्य करते हुए ग्राम में भ्रमण कराया। सभी समाजजन एक जैसी वेश भूषा में नजर आए। ग्राम में भ्रमण के दौरान सर्व प्रजापति समाज का पुष्प वर्षा कर, गले में दुपट्टा पहना कर, ठंडा खिला कर जोशी परिवार और भाजपा कार्यकर्ताओ द्वारा भव्य स्वागत किया गया। तत्पश्चात शोभायात्रा के समापन पर श्री श्रीयादें मां (शीतला माता) की महाआरती उतार कर प्रसादी वितरण की गई। स्वागत समारोह में उपस्थित समाजसेवी हेमेंद्र कुमार जोशी, झकनावदा भाजपा मंडल अध्यक्ष जितेन्द्र राठौड़, पूर्व सांसद प्रतिनिधि राजेश कॉसवा, गोपाल राठौड, शैतानमल कुमट, राजेंद्र मिस्त्री, नारायण राठौड़, आर्यन मिस्त्री, सुरेश राठौड़, फकीरचंद माली, ग्राम पंचायत झकनावदा के सचिव विनोद देवदा, गिरधारी भायल, गोपाल सोनी, अंकित देवड़ा, आदि उपस्थित रहे।

श्रद्धा के साथ मनाई शीतला सप्तमी

माही की गूंज, करवड़।

शीतला सप्तमी पर मंगलवार को करवड़ सहित आसपास के क्षेत्र में माता शीतला की विशेष पूजा अर्चना की गई। सुबह से ही मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमडी महिला श्रद्धालु विशेष रूप से सोलह श्रृंगार कर सज सवर कर पूजा की थालियां लेकर सुबह से ही मंदिर पहुंचना प्रारंभ हो गई। दर्शन एवं पूजन के लिए लंबी कतारे लगी रही। श्रद्धालुओं ने शीतला माता की विधि विधान से पूजा अर्चना कर विशेष व्यंजनों का भोग अर्पित किया। महिलाओं ने माताजी से परिवार की सुख शांति और समृद्धि की कामना की। श्रद्धालुओं में विशेष उत्साह और उमंग देखने को मिला।

परंपरा के अनुसार महिलाओं ने एक दिन पूर्व अपने घरों पर विशेष व्यंजन बनाकर तैयारी की। पर्व के दिन घरों में गैस और चुला नहीं जलाया तथा एक दिन पूर्व बना भोजन ही ग्रहण किया। साथ ही घर आने वाले मेहमानों का स्वागत भी इन्हीं ठंडे बने विशेष व्यंजनों से किया।

शीतला माता पूजन के लिए मंदिरों में लगी कतार

माही की गूंज, सारंगी।

शीतला सप्तमी पर मंगलवार को ग्राम सहित आसपास के क्षेत्र में माता शीतला की विशेष पूजा अर्चना की गई। सुबह से ही मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी विशेष रूप से महिला श्रद्धालु सोलह श्रृंगार करके माता के दर्शन पूजन के लिए मंदिर पहुंची। ग्राम के शीतला माता मंदिर पर विशेष तैयारी की गई थी। उधर महिलाओं द्वारा माताजी को लगाए जाने वाले भोग के लिए एक दिन पहले ही भोजन सामग्री व प्रसादी भोग हेतु बनाई गई थी। सप्तमी के दिन घरों में चूला नहीं जलाया जाता हे इसके चलते सोमवार को ग्राम के बाजार में बड़ी संख्या मे महिलाएं खरीदी करती नजर आई।

पूजन से रोग व्याधियों से रक्षा होती

धार्मिक मान्यतानुसार शीतला सप्तमी पर माता की पूजा करने से परिवार में सुख, समृद्धि बनी रहती है तथा रोग व्याधियों से रक्षा होती है। इसी मान्यता के चलते महिला एक दिन पहले ही घरों में भोजन तैयार कर उसे प्रसाद के रूप में सुरक्षित रखती है, अगले दिन प्रातः काल उस भोजन को माता शीतला को अर्पित कर पूजा अर्चना करती है एवं अपने परिवार , घर में सुख शांति के लिए मां से प्रार्थना करती है।

होली के एक दिन में 948 हादसों ने सरकार के सारे तंत्र, नियम, कानून और समझाईश को किया धराशाही

माही की गूंज, झाबुआ।

सड़को पर सुरक्षा का उत्तरदायित्व सरकारी सिस्टम का हारा हुआ सिद्ध हो रहा है जिसको प्रमाणित करती दुर्घटनाओं के संबंध में सामने आई रिपोर्टस् पूरा करती है। वर्तमान में एक रिपोर्ट 108 एम्बुलेंस द्वारा जारी की गई है जिसमें बताया गया कि होली के दिन पूरे प्रदेश भर में 948 हादसें हुवें। एक अनुमानित आकड़ा देखा जाए तो प्रदेश के प्रत्येक जिले में दो दर्जन से अधिक दुर्घटना घटीत हुई है।

सरकारों ने सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए बहुत से नियम, कानून बनाए किंतु हादसों की इस रिपोर्ट को देखते हैं तब प्रतीत होता है कि, सरकार को जिस स्तर पर सफलता प्राप्त होनी थी वो नहीं मिल पाई और हादसों में निरंतर वृद्धी हो रही है। लोग दुर्घटना का शिकार होकर अपनी जान गवांते या घायल हो रहे हैं। इस पर शासन प्रशासन द्वारा समझाईश के सारे उपाय फीके रहते हैं। नियम पालन करवाने के लिए प्रशासन की कठोरता और नियमों को तोड़ने पर दिया जाने वाला दंड कोई माइने नहीं रखता। क्योंकि सिर्फ एक दिन वो भी भारतीय त्योहार का जिस दिन सभी खुशियों के रंगों से अपनो को रंग कर परिवेश को प्रफुल्लित बनाते हैं उसी दिन पूरे प्रदेशभर में दुर्घटना का इतना बड़ा आकड़ा निश्चित ही गहन चिंता का विषय है। इस विषय में चिंता और अधिक तब बढ़ जाती है जब हादसों के इन आकड़ों में यह पता चलता है कि, दुर्घटना का शिकार हुए अधिकतर युवा है और तो और गंभीर चिंता का भयानक रुप भी दिखाई देता है जब इन हादसों में नाबालिग की संख्या भी होश उड़ाने वाली सामने आती है।

भारत में सड़क दुर्घटनाओं की ओर देखे तो वह आंकड़ें जो सामने आते हैं वे एक आपदा की स्थिति की तरफ संकेत देते हैं। वर्ष 2022 में सड़क दुर्घटना में 1.68 लाख लोग मौत की आगौश में चले गये। अनऔपचारिक आंकड़ो के अनुरुप देश में एक वर्ष के अंदर लगभग 3.3 लाख लोग सड़क हादसों में मारे जाते हैं। यह संख्या विश्व में कुछ देशों की जनसंख्या से भी ज्यादा है। देश में दुर्घटना के यह आंकड़े यातायात नियमों के कमजोर बुनियादी ढांचे और नागरिको के प्रति सुरक्षा की लापरवाही को उजागर करता हैं। इस समस्या का सरकार के पास कोई समाधान नहीं है, वहीं छोटे शहरों में इस समस्या की अनदेखी भी की जा रही है। एक वर्ष में इतने लोगों का मरना देश के लिए एक आपदा से कम नहीं है और देखा जाए तो सड़क दुर्घटनाएं मानवजनित आपदा है। इस मानवजनित आपदा ने प्रदेश में एक दिन में दुर्घटना के आकड़े को एक हजार के बहुत पास लाकर खड़ा कर दिया है।

शहरों में पुलिस प्रशासन की लापरवाही और आरटीओ विभाग की अनदेखी का परिणाम यह होता है कि शहरों में दुर्घटनाओं के आंकड़ों में वृद्धि होती जा रही है। होलीका उत्सव में एक दिन में हुवें इन हादसों के भयानक आकड़ों में कारण वाहन चालको में नशा, मस्ती में नियमों की अनदेखी और तेज गति से वाहन चलाना मुख्यतः सम्मिलित है साथ ही शामिल है प्रशासनिक लापरवाही, यातायात पुलिस की उन चालको के लिए अनदेखी जिन्होंने नियमों की धज्जीयां उड़ा दी। त्योहार के दिन नियम तोड़ने वालों के प्रति पुलिस की उदासीनता ने हादसों के आकड़े में जो गति प्रदान की है वो ऐतिहासिक हो गई है। यदी समय रहते सतर्कता नहीं लाई गई तब प्रदेश में होली के दिन हादसों की जिस आंकड़े की रिपोर्ट आई है उसका रिकार्ड टूटने में अधिक समय नहीं लगेगा।

पुलिस त्योहारों के समय किसी को नीजी स्थानों पर मदिरापान कर रहे लोगों को रोक नहीं सकती किंतु नशे में वाहन चलाने से तो रोका जा सकता है। त्योहार पर कोई घटना न हो इसीलिए रोक कर उनके माता-पिता या परिजनों को बता कर तब तक रोका जा सकता है जब तक की नशा उतर न जाए। यदि दंड का यह प्रारुप पुलिस अपनाती है तब भी प्रभाव पड़ेगा। नियम तोड़ने वालों पर जब भी पुलिस चालानी कार्यवाही करती है तब गलती करने वाला चालक पैसा देकर छुट जाता है, या फिर किसी नेता या अधिकारी को फोन लगवा कर छुटकारा पाता है। भ्रष्टाचार की जुड़ी नाल के कारण पुलिस भी नियम तोड़ने वालों को छोड़ना पड़ता है, पर उससे यह निश्चित नहीं होता कि, वह चालक जो किसी के कहने पर पुलिस से छुटा है वह आगे चलकर किसी नियम को तोड़ेगा नहीं। इस बात की पुष्टी तो उस चालक से भी नहीं होती जिसने अपनी गलती के पैसे दिए हो।

इसी विषय को लेकर कुछ प्रबुद्ध जनों का कहना है कि, पुलिस ने अभी तक चालानी कार्यवाही में समझाईश को दौर नहीं चलाया, और चालान भी टारगेट पूरा करने के लिए बनाए, जिसमें पुलिस अधिकरतर वाहन चैकींग करती है और वाहन संबंधित पेपर चैक करती है, जिसमें कमी पाने पर चालक पर चालानी कार्यवाही की जाती है। पुलिस को यह निश्चित करना होगा की चालक ने पांच गलती कर दी तो उसके लाइसेंस पर रेड कार्ड आ जाए ताकी अगली गलती में उसका लाइसेंस रद्द किया जा सके। वहीं नियम तोड़ने वालों की सजा भी होना चाहिए जिसे पुलिस वाहन चालक को तीन घंटे वहीं बैठा कर भूगता सके।

वर्ष में एक बार सात दिवस का यातायात सप्ताह जिसमें विद्यालयो में जाकर विद्यार्थियों को यातायात के सम्बंध में जागरुक देने से सरकार अपने कार्य को पूर्ण नहीं बता सकती। क्योंकि क्या इन सात दिनों में इतनी जागरुकता आ जाती है कि लोगों में यातायात की समझ आ जाए। अगर ऐसा होता तो केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की रिपोर्ट दुर्घटना के इतने भयानक आंकड़े नहीं होते न ही प्रदेश में 108 एम्बुलेंस होली के एक में हुए 948 हादसों की रिपोर्ट प्रस्तुत करती।

रिंकेश बैरागी

हालांकि, भरतीय समाज में परिवहन की परिभाषा और यातायात की जागरुकता शुन्य के आसपास ही बनी हुई है। जिसे बढ़ाने पर ही हादसों के आंकड़ो में कमी आएगी।

बहरहाल, समय बहता जा रहा है, समाज और सरकार किसी विशेष सुबह के सुरज की प्रतिक्षा नही करते हुवें दुर्घटनाओं के प्रति सजग हो कर सतर्क हो जाए अन्यथा हादसों की संख्या में जिस प्रकार से निरंतर बढ़ोत्तरी हो रही है उसे देख कर यही आभाष होता है कि हादसों में लाखों को हम खोते जाएगे। समाज में समझाईश की टोली तुरंत सक्रिय होकर वाहन चालको को यातायात के नियमों के बारे में बताना होगा। समाजिक संगठनों को यातायात जागरुकता कार्यक्रम करने होगे, तब कहीं यातायात के सम्बंध में जागरुकता फैलेगी और संभवत सड़कों पर होने वाले हादसों में कुछ कमी हो। वहीं सरकार को यातायात प्रबंधन और परिवहन के नियमों को पाठ्यक्रम में शामिल करना होगा जिससे भावी पीढ़ी इस आपदा से सतर्क हो और भारत में जनता सड़को पर सुरक्षित रहे।

संपादकीय

मुफ्त जमीं, महंगा इलाज

कभी चिकित्सा के पेशे को भगवान के दूसरे रूप में मानवता की सेवा का पर्याय माना जाता था। लेकिन आज मुनाफे की चांदी बटोरने की होड़ वाले अग्रणी पेशों में चिकित्सा व्यवसाय की गिनती होने लगी है। धन बटोरने की अंधी हवस में मानवता के तार-तार होने की इस व्यवसाय से जुड़ी खबरें आये दिन सुर्खियां बटोरती रहती हैं। यूं तो आज पैसे की अंतहीन भूख उन तमाम पेशों में नजर आती है जो सेवा-परोपकार व मनुष्यता के कल्याण में अग्रदूत माने जाते रहे हैं। लेकिन कुछ पेशे ऐसे हैं जो इंसानियत के रखवाले माने जाते रहे हैं। यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट को पूछना पड़ा कि दिल्ली में जिन 51 अस्पतालों को रियायती जमीन दी गई थी और उन्होंने कुछ प्रतिशत गरीबों का इलाज मुफ्त करने का वायदा किया था, वे ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं? दरअसल, केंद्र सरकार ने वर्ष 2012 में एक नीतिगत फैसला लिया था, जिसके अंतर्गत दिल्ली में गरीब लोगों के लिये निजी अस्पतालों में एक सीमा तक मुफ्त इलाज की सुविधा मुहैया कराई गई थी। कहने की जरूरत नहीं है कि अस्पताल निजी हों या सरकारी, वे सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराने के लिये ही बने होते हैं। इसी के मद्देनजर कई निजी अस्पतालों के निर्माण हेतु रियायती दर पर सरकार भूखंड उपलब्ध कराती है। जिसके चलते निजी अस्पतालों के कुछ दायित्व भी होते हैं। जिसमें निर्धन मरीजों के उपचार हेतु निःशुल्क उपचार की सुविधा उपलब्ध कराना होता है। यही वजह थी कि साल 2018 में भी, देश की शीर्ष अदालत ने रियायती जमीन हासिल करने वाले अस्पतालों को नसीहत दी थी कि गरीब लोगों को मुफ्त इलाज उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए। साथ ही इस मामले में लापरवाही बरताने वालों की जवाबदेही भी सुनिश्चित करने को कहा था। विडंबना यह है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा चेताने के बावजूद अस्पताल प्रबंधन ने मुद्दे को गंभीरता से नहीं लिया। वहीं दूसरी ओर इस बाबत निगरानी करने वाले सरकारी विभाग भी आंख मूंद कर बैठे रहते हैं।

इस गंभीर मुद्दे की बार-बार अनदेखी किए जाने से खिन्न देश की शीर्ष अदालत ने हाल ही में दिल्ली में रियायती दामों में प्लॉट लेने वाले 51 हॉस्पिटलों को नोटिस भेजकर अपना दायित्व न निभाने वालों को इसकी वजह बताने को कहा गया है। कोर्ट ने चेताया है कि अस्पताल के मालिकों के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई क्यों न शुरू की जाए! यह विडंबना है कि केंद्र व दिल्ली सरकार इस गंभीर मामले में उदासीन नजर आती हैं। विसंगति देखिए कि जिस दायित्व का निर्वहन सरकारों को करना चाहिए था, उस पर देश के सुप्रीम कोर्ट को आदेश देने पड़ रहे हैं। जो हमारे तंत्र की काहिली को ही उजागर करता है। उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार के नीतिगत फैसले में इस बात का प्रावधान था कि रियायती कीमत पर जमीन पाने वाले अस्पतालों को आंतरिक रोगी विभाग में न्यूनतम दस प्रतिशत और ओपीडी में पच्चीस प्रतिशत गरीबों का इलाज मुफ्त करना होगा। जिससे जुड़ी जवाबदेही पूरी करने को शीर्ष अदालत ने 2018 में भी चेताया था। लेकिन इसके बावजूद जमीनी हकीकत में कोई बड़ा बदलाव नहीं आया। यही वजह है कि पिछले दिनों शीर्ष अदालत ने इन अस्पतालों को नोटिस भिजवाए हैं। साथ ही अवज्ञा करने पर अवमानना की कार्रवाई की चेतावनी भी दी है। इस बात में कोई संदेह नहीं कि इन निजी अस्पतालों में गरीबों को मुफ्त इलाज मिल सके, पहली जवाबदेही सरकार की बनती है। यदि सरकार की नियामक एजेंसियां सख्ती दिखाती तो क्या मजाल थी कि निजी अस्पताल अपने वायदे से मुकर जाते। बाकायदा, ऐसे मामलों में उदासीनता दिखाने वाले सरकारी अधिकारियों की भी जवाबदेही तय होनी चाहिए और लापरवाही दिखाने वालों के खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए। निस्संदेह, इन हालातों के चलते ही आम जनता का तंत्र से भरोसा उठता है। यदि सरकारी तंत्र निगरानी व जवाबदेही तय करने में चुस्ती दिखाता तो कई गरीब मरीजों का जीवन बचाया जा सकता था। आज जीवन रक्षा से जुड़ी चिकित्सा सुविधाएं इतनी महंगी हो चुकी हैं कि हर साल लाखों लोग खर्चीले इलाज कराने के चलते गरीबी के दलदल में धंस जाते हैं।

समरसता की चेतना का पोषण दूर करेगा विभाजन

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) द्वारा प्रस्तावित नए नियमों को लेकर देशभर में विवाद पूरी तरह थमा नहीं है। बुद्धिजीवी वर्ग से लेकर शिक्षाविदों, छात्र संगठनों और आम नागरिकों तक, विभिन्न स्तरों पर इस प्रस्ताव का विरोध दिखाई दे रहा है। आलोचकों का मानना है कि इन नियमों से उच्च शिक्षा की स्वायत्तता और शैक्षणिक ढांचे पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है, जबकि सरकार और आयोग का तर्क है कि ये बदलाव शिक्षा व्यवस्था को अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाने के उद्देश्य से किए जा रहे हैं। यही कारण है कि यह मुद्दा केवल शैक्षणिक संस्थानों तक सीमित न रहकर सार्वजनिक बहस का विषय बन गया है।

इस विरोध की तीव्रता का अंदाज़ा राजधानी दिल्ली में हुए प्रदर्शनों से लगाया जा सकता है। जंतर-मंतर पर बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी एकत्रित हुए और यूजीसी द्वारा प्रस्तावित नियमों का खुलकर विरोध किया। गौरतलब है कि कुछ ही दिनों पूर्व में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की कुलपति शांतिश्री धुलिपुड़ी पंडित से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के 'प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस रेगुलेशन्स, 2026' के संदर्भ में पूछे गए प्रश्न के उत्तर ने व्यापक बहस को उत्पन्न कर दिया। अवांछित तर्कों के बीच हमें एक गंभीर विषय पर विचार करने की आवश्यकता है कि क्या वास्तव में हमारे उच्च शिक्षण संस्थानों में जाति-आधारित भेदभाव उस रूप में विद्यमान है, जिस रूप में यह प्रचारित और प्रसारित किया जा रहा है?

सत्ताईस वर्षों के अध्यापन अनुभव और हजारों विद्यार्थियों के निकट संपर्क के आधार पर मेरा अनुभव रहा है कि महाविद्यालयीन परिसर जातिगत भेदभाव से मुक्त सामाजिक संरचना का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। वहां का वातावरण मूलतः संवाद, सहभागिता और मित्रता के आधार पर विकसित होता है, जहां पारस्परिक संबंध जातिगत पहचान के बजाय मानवीय संपर्क और साझा शैक्षणिक जीवन से निर्मित होते हैं। दुर्भाग्य यह है कि भारतीय समाज आज जातिगत विमर्श के ऐसे जाल में उलझता जा रहा है, जहां पूर्व धारणाएं प्रायः तथ्यों पर भारी पड़ती प्रतीत होती हैं। हम वास्तविकताओं की शांत और गहन पड़ताल करने के बजाय प्रचलित मान्यताओं को ही अंतिम सत्य मान लेने की प्रवृत्ति विकसित कर चुके हैं।

यह भी एक व्यापक धारणा बन गई है कि भारतीय परंपराएं स्वयं जातिगत भेदभाव का पोषण करती रही हैं परंतु क्या यह सत्य है? या ऐसा कुछ है जिससे हम परिचित नहीं हैं। एएल बाशम ने 1954 में 'द वन्डर दैट वाज इण्डिया' में लिखा था कि 'मध्य युग के पूर्व भारत में जाति व्यवस्था सरल थी।' बहुत से उदाहरण ऐसे भी मिलते हैं जहां वर्ग परिवर्तित होता रहा है। कार्य को बदलने पर सामाजिक स्थिति बदलती रहती है। वैदिक वाङ्मय और प्राचीन संस्कृत साहित्य में कहीं भी जाति व्यवस्था या अस्पृश्यता के उदाहरण परिलक्षित नहीं होते हैं। शूद्र' शब्द को 'क्षुद्र' से बना हुआ मानना भाषाशास्त्रीय रूप से प्रामाणित नहीं है। इसकी व्युत्पत्ति को लेकर विद्वानों में मतभेद हैं, अतः इसे सीधे 'हीन' अर्थ से जोड़ना उचित प्रतीत नहीं होता।

अथर्ववेद के शब्दों की निरुक्ति में अपने श्रम के स्वेद (पसीने) से विविध उत्पादकीय कार्य में रत वर्ग को शूद्र कहा गया है। अर्थात परिश्रमपूर्वक विविध प्रकार की मूल्यवान वस्तुओं के उत्पादन में रत (संलग्न) रहने वाले वर्ग को शूद्र कहकर संबोधित किया गया। इसमें किंचित भी संशय नहीं कि भारत पर हुए बाहरी आक्रमणों से पूर्व अपने उत्पादन कार्यों के प्रतिफल के स्वरूप शूद्र का समाज में आर्थिक एवं सामाजिक दृष्टिकोण से उच्च स्थान था। इसलिए कामन्दक नीतिसार में कहा गया है कि राजा को नया नगर बसाते समय शूद्र जो कि विभिन्न मूल्यवान वस्तुएं उत्पादित करते हैं उन्हें व वैश्य जो उन वस्तुओं के व्यापार से आय उत्पन्न करके राजस्व बढ़ाते हैं उन्हें अधिक संख्या में बसाना चाहिए। एगंस मेड्डिसन ने अपने अध्ययन में स्पष्ट उल्लेखित किया है कि विश्व का एक-तिहाई उत्पादन भारत में होने व प्राचीन वाङ्मय के अनुसार समग्र उत्पादन का दायित्व शूद्रों के नियंत्रण में होने से ही शूद्र प्राचीन काल से ही राज्य की अर्थव्यवस्था का आधार रहे हैं। ऐसे में यह प्रश्न उठना स्वाभाविक ही है कि यकायक शूद्र निम्न श्रेणी में कैसे अवस्थित हो गए?

अगर इस प्रश्न पर गंभीरता से विचार किया जाए तो यह विदित होगा कि इस वर्ग के पास कौशल और परिश्रम की निधि थी जिसे औद्योगीकरण के प्रभाव ने समाप्त कर दिया और परिणामस्वरूप रोजगार का अभाव उनकी आर्थिक विपन्नता का कारण बना। अंग्रेजों द्वारा उन्हें यह विश्वास निरंतर दिलाया गया कि उनके साथ जो कुछ भी नकारात्मक हुआ है और हो रहा है उसका कारण श्रेष्ठी वर्ग हैं। असत्य को निरंतर दोहराने पर वह सत्य प्रतीत होने लगता है। ब्रिटिश काल में बोया गया जातिगत विभाजन का बीज धीरे-धीरे एक ऐसी बेल में परिवर्तित हो गया, जो समाज के अनेक हिस्सों में फैलता चला गया। समय के साथ हमने यह कठोर सत्य भी भुला दिया। जब-जब समाज बिखरता है तब तक राष्ट्र की शक्ति क्षीण होती है।

इतिहास साक्षी है कि आंतरिक विभाजन किसी भी देश की प्रगति को धीमा कर देता है। हमारे पूर्वजों द्वारा स्थापित 'वर्ण व्यवस्था' 'जाति व्यवस्था' का आवरण पहन समय के साथ विकृत रूप ग्रहण करती गई और बीती कई सहस्राब्दियों में उसने भारतीय समाज के मूल आदर्श सहिष्णुता, सामाजिक समरसता तथा एकत्व भाव पर कुठाराघात किया। देश की सुदृढ़ता और अखंडता को सुरक्षित रखने के लिए आवश्यक है कि हम उन विखंडित इतिहास-कथनों और विभाजनकारी आख्यानों से स्वयं को मुक्त करें, जो हमें बार-बार यह विश्वास दिलाने का प्रयास करते हैं कि हम किसी से श्रेष्ठ हैं या किसी से निम्नतर हैं।

डॉ. ऋतु सारस्वत

हमें यह स्मरण रखना होगा कि समाज किसी एक व्यक्ति, समुदाय या समूह से नहीं बनता; उसका प्रत्येक अंग राष्ट्र-निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अतः आवश्यक है कि हम जातिगत पहचान से ऊपर उठकर व्यक्ति के व्यक्तित्व, उसकी प्रतिभा और उसके चरित्र की विशेषताओं को महत्व दें। किसी भी समाज की वास्तविक उन्नति व्यक्ति की क्षमता, परिश्रम, सामाजिक उत्तरदायित्व और नैतिक दृढ़ता पर आधारित होती है, न कि जन्माधारित पहचान पर। हम यह कैसे विस्मृत कर सकते हैं कि भारत वह राष्ट्र है जिसने 'वसुधैव कुटुम्बकम्' का उद्घोष किया है। जब हमारी सभ्यता विश्व को एक परिवार के रूप में देखने का आदर्श प्रस्तुत करती है, तब जाति की संकीर्ण विचारधाराओं में उलझे हमारे ही आदर्शों की खिल्ली उड़ाते प्रतीत हो रहे हैं। ध्यान रहे कि एक ऐसा समाज, जो स्वयं को लगातार खांचों में बांटता रहता है, अंततः अपनी सामूहिक शक्ति खो देता है। इसलिए आवश्यक है कि हम विभाजन की मानसिकता को नहीं, बल्कि समरसता की चेतना को पोषित करें।

'साइलेंट किलर' बन सकता है बढ़ता तापमान

दुनिया में बढ़ती गर्मी का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। अनुमान है कि साल 2050 तक, दुनिया के लगभग 41 फीसदी लोग खतरनाक स्तर पर भीषण गर्मी का सामना करने को विवश होंगे। साल 2010 तक यह आंकड़ा महज 23 फीसदी था। यह स्थिति तब होगी जब दुनिया का औसत तापमान औद्योगिक युग से दो डिग्री सेल्सियस बढ़ जाएगा।

आक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के अध्ययन में यह खुलासा हुआ है कि भारत, नाइजीरिया, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश और फिलीपींस इससे सर्वाधिक प्रभावित होंगे। सच तो यह है कि भीषण गर्मी से स्वास्थ्य पर गंभीर खतरे हो सकते हैं, जैसे अंगों की क्रियाशीलता बाधित होना, विकलांगता, चक्कर, सिरदर्द आदि, साथ ही हृदयघात भी हो सकता है। इसके अतिरिक्त, शिक्षा, कृषि, उत्पादकता, जीवन और विस्थापन पर भी खतरा मंडरा रहा है। वैज्ञानिकों ने इसे 'साइलेंट किलर' की संज्ञा दी है।

वर्ष 2026 की शुरुआत में ही गर्मी, सूखा और आग की घटनाओं ने चेतावनी दे दी है। यह बदलाव भारत जैसे विकासशील देशों के लिए एक गंभीर संकेत है, क्योंकि भारत की विशाल आबादी और पहले से ही गर्म जलवायु इसे और अधिक संवेदनशील बना देती है। इसका मुख्य कारण 1950 के बाद से लू या हीटवेव की आवृत्ति और तीव्रता में वृद्धि है। कमजोर बुनियादी ढांचे के कारण विकासशील देशों में आर्थिक रूप से कमजोर लोग गर्मी और स्वास्थ्य जोखिमों के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं।

इंटरनेशनल लेबर आर्गेनाइजेशन के अनुसार, भारत में गर्मी के कारण उत्पादकता में भारी कमी आएगी और जीडीपी में गिरावट होने की आशंका है। वैज्ञानिकों का कहना है कि अमेरिका, चीन और भारत में 23 से 30 अतिरिक्त दिन गर्मी का सामना करना पड़ेगा।

दुनिया के शोधों ने यह साबित कर दिया है कि भीषण गर्मी से प्रभावित देशों की सूची में भारत सबसे ऊपर है। भारत के आधे से अधिक जिले भीषण गर्मी का सामना करेंगे। यह निष्कर्ष 'नेचर सस्टेनेबिलिटी' जर्नल में प्रकाशित रिपोर्ट और 'हाउ एक्सट्रीम हीट इज़ इम्पैक्टिंग इंडिया- असेसमेंट डिस्ट्रिक्ट लेवल हीट रिस्क-2025' के नाम से सीईईडब्ल्यू के अध्ययन में सामने आया है। इस अध्ययन में सबसे गर्म रातों, यानी 'हॉट नाइट्स', की तादाद में वृद्धि का उल्लेख किया गया है, जिससे हृदय रोग और उससे जुड़ी बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। हीट स्ट्रोक और हृदयाघात की संभावना भी अधिक रहती है।

वैज्ञानिकों के अनुसार, गर्मी का यह असर 1.5 डिग्री की सीमा पार करने से पहले ही दिखने लगेगा। अगले 5 वर्षों में लाखों घरों और दफ्तरों को कूलिंग सिस्टम की जरूरत में बेतहाशा बढ़ोतरी होगी। इसके परिणामस्वरूप, जहां ऊर्जा की मांग बढ़ेगी, वहीं कार्बन उत्सर्जन में भी इजाफा होगा।

गौरतलब है कि आज हम गर्मी के बढ़ते प्रभाव पर चर्चा करते हुए पर्यावरण में वृक्षों की महत्ता को नकार रहे हैं। दुख की बात यह है कि विकास के नाम पर हम हर साल लाखों हरे-भरे पेड़ों की बलि दे रहे हैं। यह सिलसिला पूरे देश में बेरोकटोक जारी है, और सरकार मौन है। राजस्थान में ग्रीन एनर्जी के नाम पर हजारों-लाखों खेजड़ी के पेड़ काटे जा रहे हैं। महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय के पर्यावरण विज्ञान विभाग के विभागाध्यक्ष के अनुसार, खेजड़ी की कटाई के कारण इस क्षेत्र का तापमान 7 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ गया है।

सीईईडब्ल्यू के अनुसार, देश में गर्मी के सबसे अधिक जोखिम वाले राज्यों में दिल्ली, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, गोवा, केरल, राजस्थान, गुजरात, कर्नाटक और तमिलनाडु शामिल हैं। देश के 417 जिले उच्च जोखिम की श्रेणी में हैं, जबकि 201 जिले मध्यम जोखिम का सामना कर रहे हैं। अब उत्तर भारत के शुष्क क्षेत्रों में भी तटीय इलाकों की उमस बढ़ रही है और सिंधु और गांगेय क्षेत्रों में पिछले दशक के मुकाबले आर्द्रता में 10 फीसदी की वृद्धि हो चुकी है। दिल्ली, कानपुर, वाराणसी, जयपुर जैसे शहरों में आर्द्रता का स्तर 40-50 फीसदी तक पहुंच चुका है।

ज्ञानेंद्र रावत

चिंताजनक पहलू यह है कि बढ़ती गर्मी का खतरा सिर्फ शहरी क्षेत्रों तक सीमित नहीं है, बल्कि उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र और केरल जैसे ग्रामीण इलाके भी इससे प्रभावित हो रहे हैं। खुले आकाश के नीचे काम करने वाले खेतिहर मजदूरों पर इसका सबसे बुरा असर पड़ता है। यूएनईएससीएपी का कहना है कि इन मजदूरों में हीट स्ट्रेस, डिहाइड्रेशन और गर्मी से संबंधित बीमारियां अधिक होती हैं, क्योंकि छाया, पानी और आराम की कमी स्थिति को और गंभीर बना देती है। उन्हें समय पर इलाज भी नहीं मिल पाता।

संयुक्त राष्ट्र ने जोर दिया है कि बढ़ती गर्मी से बचाव के लिए तुरंत ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है। इसके लिए मौसम और जलवायु जोखिम की सटीक जानकारी को निर्णय प्रणालियों और अर्ली वार्निंग सिस्टम में शामिल करना होगा। साथ ही, विभिन्न क्षेत्रों के बीच बेहतर समन्वय और इस दिशा में सार्वजनिक निवेश को बढ़ावा देना जरूरी है। यह महज एक चुनौती नहीं, बल्कि भविष्य की सुरक्षा का सवाल भी है।

पुरुषवादी वर्चस्व से संघर्ष के बाद हासिल सफलता के मायने

संभावना और हकीकत, इरादा और कर्म के बीच संशय, खुद को ढाल लेने और यहां तक कि भय का साया मंडराता रहता है। इंसान के इतिहास और वजूद की लंबी शृंखला में जितनी चीज़ें जश्न मनाने लायक हैं, उतनी ही अफ़सोस करने लायक भी। जब मैं महिला दिवस के अर्थ और अहमियत के बारे सोचता हूं, तो मुझे अहसास होता है कि कैसे पीटी उषा, मैरी कॉम, साक्षी मलिक, विनेश फोगाट और कई दूसरी खिलाड़ियों ने उस 'पुरुषवादी दृष्टि' को बदल दिया, जो उन्हें एक खास तरीके से देखने को सिखाया जाता है।

इन चारों में, सुपर एथलीट उषा, महान बॉक्सर मैरीकॉम, ओलंपिक पदक विजेता पहलवान साक्षी मलिक और कुश्ती में शोषण के खिलाफ़ प्रतिरोध का चेहरा बनी विनेश फोगाट, काफी कुछ समान है। उन्होंने ऐसी व्यवस्था में व्याप्त मुश्किलों के विरुद्ध लड़ाई की और कामयाबी पाई, जो महिलाओं व गरीब के खिलाफ़ है। बहुत कुछ हासिल करने के बावजूद, वे अभी एक ऐसे समाज में स्वीकृति पाने को संघर्षरत हैं जो महिला को कार्यस्थल व खेल मैदान में बराबर के सहयोगी की बजाय बतौर खतरा अधिक देखता है। ज़िंदगी सीखने का अनुभव है, सफ़र जो किसी की धारणा, तय सोच को चुनौती देता है। दीवार पर लगा आईना वही दिखाता है जो सामने है, लेकिन आप मनभावन ही देखना चाहते हैं। देश के करोड़ों नौजवानों की तरह, मेरे मानस में भी हिंदी सिनेमा में दिखाई जाने वाली ऐसी औरत की छवि भर गई, जिसकी जिंदगी का मकसद वफ़ादारी, निःस्वार्थ भाव, गुलामी चुनना और मर्द जीवनसाथी को सफल होने में मदद करना है। वे गोरी, नाज़ुक, अबला थीं और उन्हें दुनिया से बचाने को वीर पुरुष की ज़रूरत थी।

मैं 1979 में पत्रकारिता की दुनिया में शामिल हुआ, जहां खेल पत्रकारिता केवल मर्दों का काम था। सुना था कि किरण पेशावरिया, जिन्हें आज हम पूर्व पुलिस अफसर से राजनेता बनीं किरण बेदी के नाम से जानते हैं, एक उभरती टेनिस प्लेयर थीं, जो अपने खेल कौशल के अलावा कोर्ट पर गुस्सैल स्वभाव के लिए भी ख्यात थीं। इसकी वजह मानते थे कि वे 'कुलीन' परिवार में पली-बढ़ी 'बिगड़ैल' लड़की हैं। मेरे लिए इसका और ज़्यादा जीता-जागता उदाहरण चंडीगढ़ की नेशनल बैडमिंटन चैंपियन कंवल ठाकर सिंह और उनकी बहन किरण थीं, जिनके साथ मिल उन्होंने राष्ट्रीय डबल्स प्रतियोगिता जीती थी। आज हम किरण को बतौर फिल्म स्टार और सांसद जानते हैं। यहां भी, ज़्यादा चर्चा होती कोर्ट पर उनके नाज़-नखरे की जिसे 'विशिष्ट' पृष्ठभूमि से जोड़ा जाता था।

साल 1984 में ठेठ भारतीय हकीकत से जुड़ी एक और महिला खिलाड़ी उभरकर आयी, पीटी उषा। 'पायोली एक्सप्रेस' नाम से मशहूर यह खिलाड़ी ओलंपिक्स की 400 मीटर बाधा दौड़ में कांस्य पदक जीतने से जरा सी चूक गईं और बाद में 1986 एशियन खेलों में 4 स्वर्ण पदक जीते। उषा ने उन सब रूढ़ियों को तोड़ने की शुरुआत की थीं, जो सिनेमा व पितृसत्तात्मक समाज ने गढ़ रखी थीं। वह दुबली-पतली, सांवली, भारत के संघर्षशील कामगार वर्ग की मिट्टी में पली थीं, जिन्हें इंग्लिश तो दूर, हिंदी भी बोलनी नहीं आती थी।

साल बीतते गए और खेलों में महिलाओं का होना अब अनोखी बात नहीं और उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नाम कमाने के मामले में पुरुषों को पीछे छोड़ दिया, 2012 की एक तस्वीर मेरे दिमाग में छपी हुई है। लंदन ओलंपिक्स, जिसमें महिला बॉक्सिंग मुकाबला पहली बार शामिल किया गया था, तब पांच बार की विश्व चैंपियन मैरी कॉम ने खेल में वापसी का फैसला लिया। 29 की उम्र और दो बच्चों की मां, ओलंपिक पदक जीतने से चूकना नहीं चाहती थीं। मैं नॉवेल लेखक राहुल भट्टाचार्य के साथ राष्ट्रीय खेल संस्थान, पटियाला गया, जिन्हें एक अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका के लिए उनपर विशेष लेख लिखने का काम सौंपा गया था। ट्रेनिंग रिंग में मैरी कॉम के नाज़ुक, छोटे से शरीर को तीव्र गति वाले हाथों से ज़बरदस्त ऊर्जावान प्रहार करते देखकर मेरी सांसें थम गईं। राहुल की सहजबोध, लयदार एवं संवेदनशील अंतर्दृष्टि निर्देशित लेखनशैली-वे खासियतें जिन्होंने उनकी मशहूर किताब 'रेलसॉन्ग' में एक मज़बूत औरत (मैरी कॉम) का किरदार रोशन किया- बाद में एक लेख के रूप में सामने आईं। मैरी कॉम, जिन्होंने लंदन ओलम्पिक्स में कांस्य पदक जीता, गरीबी और हिंसा ग्रस्त मणिपुर के 'कॉम' कबीले से हैं और उनकी कहानी भारत में एक महिला होने का निचोड़ प्रस्तुत करती है, कि सिर्फ़ वही लोग जिनके पास मज़बूत इरादा व अच्छी किस्मत हों, चोटी तक पहुंचने के रास्ते की मुश्किलों से पार पा सकते हैं।

प्रदीप मैगज़ीन

मैरी कॉम की कामयाबियों पर हैरान होता हूं वहीं उनके मौजूदा कटु वैवाहिक रिश्ते, तलाक एवं पैसे की तंगी की खबर से व्यथित हूं। उनकी कहानी कई तरह साक्षी मलिक की कामयाबी व निराशा की कहानी जैसी है, जो उनकी यादों की किताब 'विटनेस' में बताई गई है। किताब में साक्षी द्वारा कुश्ती संघ अध्यक्ष के खिलाफ़ यौन-प्रताड़ना मामले में उन्हें पहुंचा संताप व निष्फल गया विरोध महसूस होता है। इसे पढ़कर समझ आता है कि मर्द वर्चस्व वाली दुनिया में लैंगिक पक्षपात के चलते, एक महिला और सफल होना कितना मुश्किल है।

विनेश फोगाट की तरह साक्षी की कहानी भी हिम्मत और हर मुश्किल के बावजूद कामयाबी पाने की है, तथापि उनकी मौजूदा ज़िंदगी पर उनके साथ हुए धोखे की छाया तारी है। उन्हें लगता है कि वे एक ऐसी व्यवस्था का शिकार हैं, जो हर हुक्म मानने पर पुरस्कृत करती है और अलग राय रखने पर दंडित। दोनों ने कुश्ती छोड़ दी, यह ऐलान दुख, निराशा और आंसुओं के बीच करना पड़ा। हालांकि, विनेश ने अपने फैसले पर पुनर्विचार कर अपना मन बदला। जब हम उनकी और कई दूसरे खिलाड़ियों की कामयाबी का जश्न मनाते हैं और पिछले साल वर्ल्ड कप में भारत की जीत पर खुश होते हैं, तो हमें इसके प्रति संवेदनशील बनने की ज़रूरत है कि मर्दों की नज़र से देखी जाने वाली दुनिया में एक औरत होने के क्या मायने हैं।

जमीन पर लेटकर गुहार लगाने पुलिस के पास पहुंची महिला

माही की गूंज, मंदसौर।

जिले में पुलिस कंट्रोल रूम में होने वाली जनसुनवाई में अक्सर लोग अपनी फरियाद लेकर पहुंचते हैं, लेकिन मंगलवार को मंदसौर पुलिस की जनसुनवाई में ऐसा नजारा देखने को मिला जिसे देखकर हर कोई हैरान रह गया। एक महिला अपने परिजनों के साथ जमीन पर लेटकर (लौट लगाकर) गुहार लगाने पहुंची. मामला जुड़ा है 5 किलो चांदी के गहनों से, जिसकी कीमत आज आसमान छू रही है।

पूरा मामला साल 2014 से जुड़ा बताया जा रहा है। जनसुनवाई में पहुंची महिला रुक्मणी बाई का आरोप है कि उसने करीब 12 साल पहले एक स्वर्णकार के पास अपने 5 किलो चांदी के आभूषण गिरवी रखे थे। महिला का दावा है कि वह कई बार स्वर्णकार विशाल सोनी के पास चक्कर लगा चुकी है, लेकिन वह उसके जेवर वापस नहीं कर रहा है। ध्यान आकर्षित करने के लिए महिला अपने परिवार के साथ जमीन पर लेटकर एसपी दफ्तर की ओर बढ़ी।

स्वर्णकार ने लगाए आरोप

वहीं, दूसरी ओर स्वर्णकार विशाल सोनी ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। विशाल का कहना है कि कहानी बिल्कुल उलट है। स्वर्णकार के मुताबिक, महिला और उसके परिजन 2014 में उससे उधार चांदी लेकर गए थे, जिसका भुगतान आज तक नहीं किया गया। बदले में पंचायत में जमीन की रजिस्ट्री करने का इकरारनामा हुआ था, जिसे महिला ने पूरा नहीं किया। स्वर्णकार ने अपने बचाव में पुलिस को पुराने बिल और लिखा-पढ़ी के तमाम दस्तावेज सौंप दिए है।

सोने-चांदी की कीमतों में उछाल के बाद सामने आ रहे ऐसे मामले

जानकारों का मानना है कि हाल के दिनों में सोने और चांदी की कीमतों में जो अप्रत्याशित उछाल आया है, उसकी वजह से सालों पुराने लेन-देन के विवाद अब पुलिस की चौखट तक पहुंच रहे हैं। जब जेवर रखे गए थे, तब कीमतें कुछ और थीं और आज बाजार का गणित पूरी तरह बदल चुका है।

मंदसौर के एएसपी टीएस बघेल ने बताया कि, जनसुनवाई में कुल 30 आवेदन प्राप्त हुए हैं। लेनदेन के अधिकतर मामले हैं। लगाए गए आरोपों की भी जांच की जा रही है। चूंकि यह लेन-देन का मामला है, इसलिए दोनों पक्षों के दस्तावेजों और आरोपों की सत्यता जांची जाएगी। जांच के बाद नियमानुसार उचित कार्रवाई की जाएगी।

बाहुबली पहाड़ी की आग में घिरने से युवक की मौत

माही की गूंज, रतलाम।

गर्मी शुरू होते ही उदयपुर की पहाड़ियों पर आग लगने की घटनाएं एकाएक बढ़ गई है। सोमवार शाम शहर के नजदीक बड़ी झील किनारे बाहुबली हिल पर लगी आग में घिरने से रतलाम जिले के उपरवाड़ा निवासी एक युवक की मौत हो गई। उदयपुर पुलिस ने बताया रतलाम का युवक उदयपुर घूमने गया था। इसी दौरान वह बाहुबली हिल पहुंचा, जहां पहाड़ी पर आग से वह चारों तरफ से घिर गया। उसे आग से बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिला और दम घुटने से मौत हो गई। अब पुलिस मामले की जांच कर रही है।

रेस्क्यू टीमें मौके पर पहुंची

उदयपुर पुलिस ने बताया कि घटना में मृतक युवक रतलाम जिले के ऊपरवाड़ा जावरा निवासी माखन सिंह पुत्र मांगू सिंह (33) वर्ष है। वह सोमवार शाम को पहाड़ी की ऊंचाई पर पहुंचा था। पहाड़ी पर आग बढ़ने पर उसने निकलना चाहा, लेकिन चारों ओर आग फैलने पर रास्ता नहीं मिल पाया। उसने आपात मदद के लिए कॉल भी किया। जब रेस्क्यू टीमें मौके पर पहुंची तब तक वह बेहोश हो चुका था। उसे बेसुध हालात में ही उदयपुर के एमबी हॉस्पिटल पहुंचाया गया, जहां मंगलवार सुबह उसने दम तोड़ दिया। माखन सिंह एक निजी कंपनी में जॉब करता था। उसके 3 बच्चे हैं।

रातभर तैनात रही टीमें

उदयपुर के फायर ऑफिसर बीएल चौधरी ने बताया कि सोमवार रात लगी आग से बाहुबली हिल क्षेत्र का करीब 3 हेक्टेयर हिस्सा प्रभावित हुआ। रात का समय था और आग बहुत ज्यादा थी। ऐसे में पहाड़ी का पूरा क्षेत्र धुएं की आगोश में आ गया था। करीब आधा किलोमीटर जंगल का हिस्सा बुरी तरह से प्रभावित हो चुका था। हालांकि देर रात 12 बजे तक आग पर काबू पा लिया गया था। एहतियात के तौर पर रातभर टीमें हिल पर ही तैनात रखी गई जिससे फिर से आग फैले तो उसे रोका जा सके।

पत्नी को मत छोड़ना...

माही की गूंज, रतलाम।

थाना स्टेशन रोड क्षेत्र के उकाला रोड निवासी 30 वर्षीय मोईन काजी पुत्र अनीस काजी ने जहरीला पदार्थ खाकर अपनी जान दे दी। मरने से पहले मोईन ने करीब सात मिनट का एक वीडियो बनाया, जो देर रात करीब 1 बजे इंटरनेट मीडिया पर वायरल हो गया। मृतक ने वीडियो किसे भेजा था, इसकी जानकारी फिलहाल सामने नहीं आ सकी है। पुलिस ने मार्ग कायम कर मामले की जांच शुरू कर दी है। घटना मंगलवार दोपहर करीब 4 बजे कि बताई जा रही है।

मोईन काजी ने मरने से पहले बनाए वीडियो में अपनी पत्नी फरहीन से बातचीत करते हुए कई बातें कही हैं। वीडियो में वह पत्नी से कहता दिखाई दे रहा है कि वह उनके बीच के विवाद को बातचीत से सुलझाना चाहता था, लेकिन पत्नी अपने भाई और माता-पिता को बुलाकर उनके साथ चली गई। इसके बाद ससुराल पक्ष द्वारा उसे डराने-धमकाने का भी आरोप लगाया गया है।

वीडियो में मोईन यह भी कहता है कि वह मजबूरी में यह कदम उठा रहा है और चाहता है कि उसके बच्चे खुश रहें। वह अपनी 13 साल की शादी का जिक्र करते हुए कहता है कि कई बार उसकी पत्नी मायके चली जाती थी और उसे बच्चों से बात भी नहीं करने देती थी। वीडियो में वह जहर की गोलियां दिखाते हुए कहता है कि उसके ऊपर कोई कर्ज नहीं था, बल्कि पारिवारिक विवाद के कारण वह परेशान था।

पत्नी और ससुराल पक्ष को ठहराया जिम्मेदार

मोईन ने वीडियो में अपनी पत्नी और ससुराल पक्ष को अपनी मौत के लिए जिम्मेदार ठहराते हुए प्रशासन से उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग भी की है। साथ ही उसने अपने बच्चों की जिम्मेदारी अपनी मां और भाइयों को देने की बात कही है।

पुलिस ने शुरू की जांच

यह वीडियो रात में वाट्सएप ग्रुपों में वायरल हो गया। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। शव का पोस्टमार्टम बुधवार को कराया जाएगा, जिसके बाद शव स्वजनों को सुपुर्द किया जाएगा।

पालक महासंघ ने स्कूलों की व्यवस्था सुधारने हेतु दिया ज्ञापन

माही की गूंज, शाजापुर।

पालक महासंघ मध्य प्रदेश की जिला इकाई शाजापुर द्वारा प्राइवेट स्कूलों की मनमानी रोकने और सरकारी स्कूलों की व्यवस्था सुधारने हेतु कलेक्ट्रेट जनसुनवाई में ज्ञापन दिया। कार्यकर्ताओं ने जिला शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए तथा प्राइवेट स्कूलो पर पांच सूत्री और सरकारी स्कूलों पर पांच सूत्री, कुल 10 सूत्री मांगों पर कलेक्टर के नाम ज्ञापन दिया।

जिलाध्यक्ष राजेश सिसनोरिया ने बताया कि, पालक महासंघ पिछले दो वर्षों से शिक्षा में अनियमितता और सुधार के लिए लगातार आवेदन और निवेदन करता आया हैं, नए सत्र की शुरुआत होने से पहले ही हम तीसरी बार जिला कलेक्टर और जिला शिक्षा अधिकारी को शिक्षा में सुधार के लिए फिर से ज्ञापन के माध्यम से निवेदन कर रहे हैं,

प्राइवेट स्कूलो के लिए हमारी प्रमुख मांग है कि कक्षा पहली ली से बाहरवीं तक एनसीईआरटी की किताबें लागू हो, फीस रेगुलेशन नियम फॉलो हो, महंगे कोर्स ओर ड्रेस पर स्कूल कमीशन बंद हो। हमारी सरकारी स्कूलों के लिए मांग है कि शिक्षक ई अटेंडेंस का पालन नहीं कर रहे हे और ना ही समय पर स्कूल खोल रहे ना समय पर स्कूल बंद कर रहे। गरीब और कमजोर बच्चों की शिक्षा में सुधार के लिए लापरवाह शिक्षकों पर कड़ी कार्यवाही हो। जिला महासचिव राजेंद्र चौखुटिया ने बताया कि जिला प्रशासन को पहले भी अवगत कराया था कि एजी तख्तवाला ओर सोलंकी ड्रेसेस पर सभी बड़े स्कूलों की ड्रेस ओर कोर्स बिक रहे ओर स्कूल वही से खरीदने के लिए मजबूर कर रहे लेकिन प्रशासन सुन नहीं रहा। यदि हमारी मांग नहीं मानेंगे तो हम आने वाले समय में बड़ा आंदोलन करेंगे। वही कार्यकारणी सदस्य मनोहर कटारिया ने बताया कि संगठन ने दो महीने पहले तीन स्कूलों की शिकायत की थी जिनके द्वारा बलात्कारी आसाराम का प्रचार प्रसार स्कूलों के बच्चों के सामने किया गया था, लेकिन जिला प्रशासन इतना निर्लज है कि स्कूल वालों को बचाने में लगा है। यदि इनमें शिक्षा का दृष्टिकोण ऐसा हे तो शिक्षा के केंद्र बंद कर देना चाहिए क्यों जनता के टैक्स से तनख्वा ले रहे हो और पालकों की जेब खाली कर रहे हो।

ज्ञापन में जिला अध्यक्ष राजेश सिसनोरिया, महासचिव राजेंद्र चौखुटिया, कार्यकारणी सदस्य मनोहर कटारिया, शिवनारायण धारिया, जिला उपाध्यक्ष नन्द किशोर पवार, जिला संगठन मंत्री नवीन पटोंदा, जिला मीडिया प्रभारी महेंद्र सौराष्ट्रीय, टी आर सिसोदिया, एडवोकेट अशोक कुमार मालवीय, संतोष मालवीय आदि के साथ अन्य पालक मौजूद रहे।

प्राचार्यों को मिला आवारा कुत्ते भगाने का जिम्मा

भोपाल।

मध्य प्रदेश के विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में छात्रों को आवारा मवेशियों और कुत्तों से अब छुटकारा मिलने वाला है। मध्यप्रदेश उच्च शिक्षा विभाग ने प्रदेश के कॉलेजों में आवारा पशुओं एवं कुत्तों के प्रवेश को रोकने के लिए गाइडलाइन जारी की है।

ये गाइडालाइन सराकरी और निजी दोनों विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में लागू होगी। मध्य प्रदेश शासन ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों को पालन करते हुए ये फैसला लिया हैं। इस नई व्यवस्था के लागू हो जाने से किसी भी शैक्षणिक संस्थानों आवारा कुत्ते और मवेशी नजर नहीं आएंगे।

नए नियमों के तहत अब कॉलेज के प्राचार्यों को ही नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है, जिनकी सीधी जिम्मेदारी कैंपस को पशु मुक्त रखने की होगी। प्राचार्यों को 16 मार्च तक सुरक्षा व्यवस्था की रिपोर्ट सौंपनी होगी। उच्च शिक्षा विभाग द्वारा नोडल अधिकारी का नाम और मोबाइल नंबर संस्थानों के प्रमुख स्थान पर प्रदर्शित करने को कहा गया है ताकि जरूरत पड़ने पर तुरंत संपर्क किया जा सके।

शिक्षा विभाग ने जिन कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में बाउंड्रीवॉल नहीं हैं, वहां दीवार निर्माण कराने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं जिन संस्थानों में बाउंड्रीवॉल क्षतिग्रस्त है वहां पर तुरंत मरम्मत कराने के आदेश दिए गए हैं। यदि किसी कॉलेज या विश्वविद्यालय परिसर में आवारा कुत्ते या अन्य पशु दिखाई देते हैं, तो संबंधित संस्थान को तुरंत स्थानीय निकाय से संपर्क कर उन्हें हटाने की कार्रवाई करनी होगी।

ई-एफआईआर व्यवस्था की रफ्तार धीमी

माही की गूंज, रतलाम।

रतलाम जिले में नागरिकों की सुविधा के लिए शुरू की गई ई-एफआइआर व्यवस्था अपेक्षित गति नहीं पकड़ सकी है। 1 जुलाई 2024 से लागू इस व्यवस्था के तहत अब तक केवल 344 ई-एफआइआर दर्ज हुई हैं। पुलिस अधिकारियों के अनुसार यह संख्या काफी कम है, जो इस सुविधा के प्रति लोगों में जागरूकता की कमी को दर्शाती है।

हालांकि पुलिस का कहना है कि ई-एफआइआर प्रणाली नागरिकों को घर बैठे शिकायत दर्ज कराने की सुविधा देती है और इससे पुलिस कार्रवाई भी तेज हो सकती है। अब पुलिस प्रशासन इस व्यवस्था को लेकर लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए विशेष अभियान चलाने की तैयारी कर रहा है।

ई-एफआइआर से घर बैठे दर्ज कर सकते हैं शिकायत

पुलिस के अनुसार ई-एफआइआर व्यवस्था के माध्यम से नागरिक चोरी, गुमशुदगी और एक लाख रुपये से अधिक की साइबर धोखाधड़ी से जुड़े मामलों की शिकायत ऑनलाइन दर्ज कर सकते हैं। इसके लिए मध्यप्रदेश पुलिस के नागरिक सेवा पोर्टल पर जाकर शिकायत दर्ज करनी होती है। ऑनलाइन शिकायत दर्ज होने के बाद उसकी सूचना सीधे संबंधित थाने तक पहुंच जाती है और पुलिस प्रारंभिक कार्रवाई शुरू कर देती है।

तीन दिन में थाने पर पहुंचना जरूरी

ई-एफआइआर दर्ज होने के बाद शिकायतकर्ता को तीन दिन के भीतर संबंधित थाने में उपस्थित होना अनिवार्य होता है। इस दौरान पुलिस शिकायतकर्ता से संपर्क कर घटना से जुड़ी आवश्यक जानकारी प्राप्त करती है। थाने में उपस्थित होने के बाद शिकायतकर्ता के हस्ताक्षर लिए जाते हैं और इसके बाद मामले की जांच आगे बढ़ाई जाती है। यदि शिकायतकर्ता तय समय में थाने नहीं पहुंचता है तो ऐसी स्थिति में शिकायत को अस्वीकार भी किया जा सकता है।

ऐसे कर सकते हैं ई-एफआइआर दर्ज

ई-एफआइआर दर्ज करने के लिए नागरिकों को मोबाइल या कंप्यूटर के माध्यम से नागरिक सेवा पोर्टल पर लॉगिन करना होता है। इसके बाद शिकायत का प्रकार चुनकर घटना का स्थान, समय और पूरा विवरण दर्ज करना होता है। आवश्यक दस्तावेज या जानकारी अपलोड करने के बाद शिकायत ऑनलाइन सबमिट की जाती है। इसके बाद शिकायत संबंधित थाने को भेज दी जाती है और पुलिस जांच की प्रक्रिया शुरू करती है।

जागरूकता के लिए चलाया जाएगा अभियान

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि अभी कई लोगों को ई-एफआइआर सुविधा की जानकारी नहीं है। इसी कारण शिकायतों की संख्या अपेक्षाकृत कम है। इसे देखते हुए पुलिस अब थाना स्तर पर प्रचार-प्रसार करेगी। इसके अलावा स्कूलों और कॉलेजों में भी जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कर नागरिकों को इस सुविधा के बारे में जानकारी दी जाएगी।

रिपोर्ट में देरी पर मांगा स्पष्टीकरण

हाल ही में बाइक चोरी के मामलों में रिपोर्ट दर्ज करने में देरी को लेकर पुलिस प्रशासन ने संज्ञान लिया है। एएसपी विवेक कुमार लाल ने थाना स्टेशन रोड और थाना दीनदयाल नगर से स्पष्टीकरण मांगा है। साथ ही सभी थानों को फरियादियों के साथ सरल व्यवहार करने और समय पर रिपोर्ट दर्ज करने के निर्देश दिए हैं।

पुलिस चलाएगी जागरुकता अभियान

एएसपी विवेक कुमार लाल के अनुसार ई-एफआइआर व्यवस्था नागरिकों को त्वरित सुविधा देने के उद्देश्य से शुरू की गई है। इसके माध्यम से लोग घर बैठे शिकायत दर्ज कर सकते हैं। अभी कई नागरिकों को इसकी जानकारी नहीं है, इसलिए पुलिस लगातार जागरूकता बढ़ाने का प्रयास कर रही है।

बच्चों से शौचालय साफ करवाने पर कार्रवाई

माही की गूंज, शाजापुर।

शासकीय एकीकृत माध्यमिक विद्यालय पिपल्यागोपाल से जुड़ी गंभीर शिकायत सामने आने के बाद प्रशासन ने कार्रवाई की है। विद्यालय के बच्चों से शौचालय की सफाई करवाने का मामला उजागर हुआ था। जिला शिक्षा अधिकारी राजेन्द्र शिप्रे ने बताया कि जांच के लिए दल गठित किया गया था।

प्राथमिक शिक्षक निलंबित

जांच में दोषी पाए जाने पर प्राथमिक शिक्षक फजल अहमद खान को मध्य प्रदेश सिविल सेवा नियम 1966 के तहत निलंबित कर दिया गया है। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय मो. बड़ोदिया रहेगा तथा उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता मिलेगा। वहीं, अतिथि शिक्षक संदीप मालवीय का कार्य व्यवहार आदर्श शिक्षक के अनुरूप न पाए जाने पर उनकी सेवाएं समाप्त कर दी गईं।

भविष्य के लिए चेतावनी

इसके अतिरिक्त माध्यमिक शिक्षक एवं प्रभारी प्रधान अध्यापक शबाना परवीन को स्टाफ पर नियंत्रण नहीं रखने के कारण भविष्य में सतर्क रहकर दायित्व निभाने के लिए अनुशासनात्मक कार्रवाई के निर्देश जारी किए गए हैं।

ईरान-इजराइल युद्ध का असर, कमर्शियल गैस सिलेंडर की आपुर्ति प्रभावित

माही की गूंज, बड़वानी।

ईरान-इजरायल के बीच बढ़े तनाव का असर अब देश के कई हिस्सों के साथ बड़वानी जिले में भी दिखाई देने लगा है। जिले में व्यावसायिक एलपीजी गैस सिलेंडरों की आपूर्ति प्रभावित हो गई है और बाजार में 19 किलो वाले सिलेंडर की कमी देखी जा रही है। इससे होटल, रेस्टोरेंट और अन्य खान-पान से जुड़े व्यवसायियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

हाल ही में 7 मार्च से गैस सिलेंडरों की कीमतों में भी वृद्धि की गई है। घरेलू गैस सिलेंडर पर 60 रुपये और व्यावसायिक सिलेंडर पर 115 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। वर्तमान में शहर में घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत करीब 958 रुपये 50 पैसे और व्यावसायिक सिलेंडर की कीमत लगभग 2053 रुपये बताई जा रही है।

जिले में गैस उपभोक्ताओं की संख्या भी काफी अधिक है। जिले में कुल 26 गैस एजेंसियां हैं और करीब 2 लाख 81 हजार से अधिक उपभोक्ता जुड़े हुए हैं। इनमें लगभग 91 हजार घरेलू कनेक्शन और करीब 1 लाख 90 हजार उज्ज्वला योजना के कनेक्शन शामिल हैं।

व्यावसायिक सिलेंडरों की कमी के कारण होटल, कैफे और भोजनालय संचालकों के सामने ईंधन का संकट खड़ा हो गया है। कुछ स्थानों पर घरेलू गैस सिलेंडरों के व्यावसायिक उपयोग की आशंका भी बढ़ रही है। वहीं घरेलू गैस सिलेंडरों का वितरण वाहनों के माध्यम से घर-घर किया जा रहा है।

जिला आपूर्ति अधिकारी भरतसिंह जमरे ने बताया कि फिलहाल व्यावसायिक गैस सिलेंडरों की उपलब्धता सीमित है। ऐसे में निजी अस्पतालों और आपातकालीन सेवाओं को प्राथमिकता देते हुए गैस उपलब्ध कराई जा रही है। उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए नियंत्रण कक्ष में दो निरीक्षकों की भी जिम्मेदारी तय की गई है।

वहीं जिले में पेट्रोल और डीजल की खपत फिलहाल सामान्य बनी हुई है और पेट्रोल पंपों पर आपूर्ति सुचारु रूप से जारी है। फिलहाल पेट्रोल-डीजल की कोई विशेष कमी नहीं बताई जा रही है।

कुएं से तीन मासूम बच्चों के शव मिले

माही की गूंज, खरगोन।

जिले के सनावद थाना क्षेत्र के अंतर्गत मलगांव और भोमवाड़ा के बीच स्थित एक खेत के कुएं से तीन मासूम बच्चों के शव बरामद हुए हैं। घटना के समय बच्चों के माता-पिता मजदूरी करने गए हुए थे। सूचना मिलने पर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और शवों को परीक्षण के लिए अस्पताल भेज दिया गया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार मलगांव निवासी मुकेश भमोरिया के खेत में एक परिवार मजदूरी करने के लिए आया हुआ था और वहीं रह रहा था। घटना के समय बच्चों के परिजन मजदूरी पर गए हुए थे और तीनों बच्चे घर पर ही थे।

खेत में पहुंचे अन्य लोगों ने जब कुएं में बच्चों के शव देखे तो तुरंत पुलिस को सूचना दी। इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को कुएं से बाहर निकलवाया।

कुएं से मिले तीनों बच्चों की उम्र बहुत कम बताई जा रही है। मृतकों में करण (उम्र 4 वर्ष), अर्जुन (उम्र ढाई वर्ष) और एक 20 दिन का शिशु शामिल है।

सूचना मिलते ही बड़वाह अनुविभागीय पुलिस अधिकारी अर्चना रावत और सनावद थाना प्रभारी धर्मेंद्र यादव घटनास्थल पर पहुंचे। उनके साथ तहसीलदार केसी सोलंकी भी मौजूद रहे। पुलिस ने शवों को कुएं से निकलवाकर अस्पताल भिजवाया है और फिलहाल इस पूरे मामले के सभी पहलुओं की जांच की जा रही है।

आदिवासी समाज ने निभाई गुड़तोड़ परंपरा

माही की गूंज, खरगोन।

जिले के धुलकोट गांव में आदिवासी भिलाला समाज द्वारा शीतला सप्तमी के अवसर पर पारंपरिक गुड़तोड़ कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बाजार चौक में आयोजित इस कार्यक्रम में समाज के लोगों ने विधि-विधान से भूमि पूजन कर लगभग 12 फीट ऊंचे खंभे की स्थापना की और उसकी पूजा-अर्चना की। इस दौरान दरबार समाज के पटेल विजयसिंह सोलंकी सहित कई समाजजन उपस्थित रहे।

परंपरा के अनुसार खंभे के ऊपरी हिस्से पर गुड़ और चने की पोटली बांधी गई थी। इस पोटली को उतारने के लिए युवाओं के बीच उत्साह और रोमांच देखने को मिला। ढोल-मादल की धुन पर युवा नृत्य करते रहे और समाजजनों की अनुमति मिलने के बाद युवक खंभे पर चढ़ने लगे। वहीं युवतियों और महिलाओं ने गुड़ की पोटली की रक्षा करने के लिए युवकों पर सोंटी से प्रहार किए। इसके बावजूद युवकों की टोली सोंटियों से बचते हुए पोटली तक पहुंचने का प्रयास करती रही।

इस आयोजन में मंडलोई और मोरे परिवार की विशेष भागीदारी रही। कार्यक्रम में खरगोन के अलावा बड़वानी, बुरहानपुर और खंडवा जिलों से भी बड़ी संख्या में आदिवासी भिलाला समाज के लोग शामिल हुए। बताया जाता है कि इस परंपरा में तीन हजार से अधिक लोगों ने भाग लिया।

समाज के बुजुर्गों के अनुसार यह परंपरा लगभग डेढ़ सौ वर्षों से चली आ रही है और हर वर्ष शीतला सप्तमी पर पूरे उत्साह के साथ मनाई जाती है। गांव के पटेल विजयसिंह सोलंकी ने बताया कि यह आयोजन समाज की एकता, परंपरा और सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक है।

आग से 6 मकान जलकर खाक, 20 बकरियां जिंदा जली

माही की गूंज, खंडवा।

बुधवार को भीषण आग लगने से छह मकान जलकर पूरी तरह खाक हो गए। आग की चपेट में आने से घरों में रखा गृहस्थी का सामान भी जल गया। घटना में लगभग 20 बकरियां भी जिंदा जल गईं। मौके पर उनकी अस्थियां दिखाई दे रही हैं। सूचना मिलने पर पहुंची अग्निशमन वाहन ने आग पर काबू पाया।

घटना पंधाना तहसील की शेखपुरा ग्राम पंचायत के जामली खुर्द खापरी गांव की बताई जा रही है। यहां धनतर मामा के फाल्या में एक ही परिवार के छह मकानों में अचानक आग लग गई। घटना के समय परिवार के सदस्य गेहूं की कटाई के लिए मजदूरी करने गए हुए थे। आग लगने की घटना दोपहर करीब एक बजे की बताई जा रही है। सूचना मिलने पर अग्निशमन दल मौके पर पहुंचा और काफी प्रयास के बाद आग पर नियंत्रण पाया। इस दौरान ग्रामीणों ने भी आग को फैलने से रोकने के लिए प्रयास किए। ग्रामीणों ने ट्रैक्टरों की सहायता से खेतों में कल्टीवेटर चलाकर आग को आगे बढ़ने से रोका, जिससे आसपास खड़ी गेहूं की फसल को बचाया जा सका।

नरवाई जलाने पर किसान पर 15 हजार रुपए का जुर्माना

माही की गूंज, खंडवा।

खंडवा जिले में खेतों में नरवाई जलाने के मामले को गंभीरता से लेते हुए प्रशासन ने कार्रवाई की है। पंधाना तहसील के ग्राम पाबई खुर्द में गेहूं की नरवाई जलाने पर किसान हेमराज पिता मेहताप सिंह, निवासी इंदौर पर 15 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है।

जानकारी के अनुसार किसान ने करीब 10 एकड़ भूमि में गेहूं की फसल की कटाई के बाद खेत में बची नरवाई में आग लगा दी थी। आग लगते देख ग्रामीणों ने इसकी सूचना पटवारी को दी। इसके बाद पटवारी आकृति मेहता, रोजगार सहायक और कोटवार की मौजूदगी में मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया गया और पंचनामा तैयार किया गया।

जांच में नरवाई जलाने की पुष्टि होने पर पंधाना तहसीलदार दिवाकर सुल्या ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के निर्देशों के तहत किसान को कारण बताओ सूचना पत्र जारी करते हुए पर्यावरण क्षतिपूर्ति के रूप में 15 हजार रुपए का चालान किया।

कृषि विभाग ने किसानों से नरवाई नहीं जलाने की अपील करते हुए बताया कि इससे मिट्टी की उर्वरता और पर्यावरण को नुकसान होता है। किसानों को नरवाई प्रबंधन के लिए वैकल्पिक उपाय अपनाने की सलाह दी गई है।

यात्री बस अनियंत्रित होकर खेत में घुसी, कई यात्री घायल

माही की गूंज, बड़वानी।

अंजड़ थाना क्षेत्र अंतर्गत राजू गांधी नगर के पास खरगोन से बड़वानी आ रही एक यात्री बस अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खेत में घुस गई। इस दुर्घटना में कई यात्रियों को चोटें आई हैं। हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया।

जानकारी के अनुसार 'मां शक्ति बस' (क्रमांक एमपी 37 पी 1711) सुबह खरगोन से बड़वानी की ओर आ रही थी। बस में लगभग 30 से अधिक यात्री सवार थे। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार बस का हैंडल लॉक अचानक टूट गया, जिससे चालक बस पर नियंत्रण नहीं रख पाया और बस सड़क से उतरकर खेत में चली गई।

दुर्घटना के बाद स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और घायलों की मदद की। हादसे में घायल छह यात्रियों को तुरंत राजपुर स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया। ड्यूटी पर मौजूद चिकित्सक ने घायलों का प्राथमिक उपचार किया। इनमें से दिनेश पिता बाबूलाल को गंभीर चोटें आने के कारण जिला अस्पताल बड़वानी भेजा गया, जबकि अन्य घायलों का उपचार राजपुर स्वास्थ्य केंद्र में ही किया गया।

घायलों में प्यारसिंह निवासी चितावल, दिनेश निवासी सुन्दरेल, बबिता मोरे निवासी जोबट, बस चालक रवि निवासी खरगोन और विकास निवासी खरगोन शामिल बताए जा रहे हैं। चिकित्सकों के अनुसार अन्य यात्रियों को मामूली चोटें आई हैं और उनकी स्थिति सामान्य है।

सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। पुलिसकर्मी गजेंद्र ठाकुर ने घायलों को अस्पताल पहुंचाने में सहयोग किया। कुछ घायलों को अंजड़ अस्पताल भिजवाया गया, जबकि अन्य को राजपुर स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया।

बताया जा रहा है कि बस चालक की सूझबूझ के कारण बड़ा हादसा टल गया, अन्यथा गंभीर जनहानि हो सकती थी। फिलहाल पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और दुर्घटना के कारणों की जानकारी जुटाई जा रही है।

उम्मीदों के उफान के बीच उपजा विकल्प

हाल ही में, नेपाली राजनीतिक हलकों में एक शब्द वायरल हुआ, 'पॉप्युलिज़्म'। लोकलुभावनवाद कोई नया शब्द नहीं है। यह शब्द लैटिन में इस्तेमाल, 'पॉपुलस' से आया है, जिसका अर्थ है, 'लोग'। 18वीं शताब्दी के मध्य में रूस के ज़ार को उखाड़ फेंकने के लिए हुए 'नरोदनिकी आंदोलन' ने 'लोकलुभावनवाद' शब्द को एक राजनीतिक रूप दिया। रूसी में 'नरोद' का अर्थ है, 'आदमी'। हालांकि, यह माना जाता है कि अमेरिका में इस शब्द का राजनीतिक विस्तार अमेरिकन पीपुल्स पार्टी द्वारा किया गया था, जिसकी स्थापना 1890 में हुई थी।

मोनाश यूनिवर्सिटी, ऑस्ट्रेलिया के प्रोफेसर बेंजामिन मोफिट की पुस्तक 'द ग्लोबल राइज ऑफ पॉपुलिस्म', 2016 में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा प्रकाशित की गई थी। इसके प्रकाशन के समय विश्व राजनीति ध्रुवीकरण की अवधि से गुजर रही थी, जिसे ब्रिटेन में ब्रेक्सिट, अमेरिका में डोनाल्ड ट्रम्प का उदय और यूरोप, लैटिन अमेरिका में दक्षिणपंथी व वामपंथी ताकतों के प्रारम्भ और पतन द्वारा चिन्हित किया गया था। लेखक बेंजामिन मोफिट ने राजनीति को ग्लैमर या शैली के रूप में वर्णित किया है, जिसकी पसंद लगभग नेपाली राजनीतिक हस्तियों के समान है। शैली, स्वाद, भोजन, चलने, बोलने या समग्र लोकलुभावन कल्पना के अनुरूप।

इस हिमालयी देश में चुनावों ने एक तरह से स्पष्ट जनादेश दिया है, अब केवल घोषणापत्र के वादों को लागू करना बाक़ी है। नेपाली मतदाताओं ने मुख्यधारा के दलों के भविष्य को लगभग सील कर दिया है। समाजवादी टोपी हर किसी के लिए उपयुक्त है, लेकिन लोकलुभावन टोपी हर किसी के लिए उपयुक्त नहीं हो सकती है। बालेन, रवि और गगन की तरह हर कोई लोकप्रिय होना चाहता है। क्योंकि, डिजिटल फ्रेम की लोकप्रियता ने जीवन की गुणवत्ता को स्क्रीन के अनुकूल बना दिया है।

नेपाली मनःस्थिति हम भारतीयों से भिन्न नहीं है। जितनी जल्दी हम हतोत्साहित होते हैं, उसी त्वरा से हम उत्साहित भी महसूस करते हैं। राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी (रास्वापा) जिसका जन्म 2017 में हुआ था, जो अपने जन्म के छह महीने के भीतर आम चुनाव में चौथी पार्टी के रूप में उभरी थी। अब यही राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी अभूतपूर्व जीत के साथ अति उत्साह में है। इनके शैदाई, 'राम राज्य' के सपने में डूबे हुए हैं।

विवादों से घिरे भूतपूर्व पत्रकार रबी लामिछाने और रैपर से राजनेता बने बालेन शाह की जोड़ी ने सोचा नहीं होगा कि संसद में इतनी सीटें आ जाएंगी कि सरकार गठन के लिए किसी दल-जमात की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। नेपाल की राजनीति के तीनों 'बिग बी', नेपाली कांग्रेस के अध्यक्ष गगन थापा, नेकपा एमाले के अध्यक्ष केपी शर्मा ओली और नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के चेयरमैन प्रचंड ने भी नहीं सोचा था कि निचले सदन 'प्रतिनिधि सभा' में केवल 17, सात, और आठ सीटें क्रमशः मिलेंगी।

नेपाल के विश्लेषक इसे 'नयां शक्ति' बोलते हैं। एक तरफ रवि लामिछाने द्वारा बनाया गया रास्वापा है, जिसमें उनका संगठनात्मक प्रभाव है। दूसरी ओर, बालेन की क्रेजिक अभूतपूर्व जीत, रास्वपा की एक उन्मादी लहर पर है। दोनों महत्वाकांक्षी हैं। वैसी स्थिति में रवि-बालेन संबंध कब तक, कितना निभेगा? बड़ा सवाल है। नेपाली जनता ने इस पार्टी के पक्ष में वोट क्यों दिया? बहुत साफ़ है, कि मतदाता का धैर्य और विश्वास पुराने नेताओं पर से टूट चुका था। सोशल मीडिया पर विराजे कुछ तुक्केबाज़ कयास लगाते हैं कि यह चीन का किया धराया है। कुछ को शक अमेरिका पर है। लेकिन, सच यह है कि नेपाल के मतदाताओं ने मत पत्र के ज़रिये मौन सजा दी है। यह उन्होंने दुनिया भर में दर्ज़ कराया है, कि बैलेट पेपर पर भरोसा कीजिये।

यह पहली बार नहीं है, जब नेपाली राजनीति में एक वैकल्पिक शक्ति की खोज की गई। हर बार जब कोई राजनीतिक बदलाव होता है, तो लोग उत्साहित होते हैं। लेकिन, जब उन अपेक्षाओं को पूरा नहीं किया जाता है तो यह असंतोष और निराशा में रूपांतरित हो जाता है। 2007 से कांग्रेस परिवर्तन के साधन के रूप में उभरी है। 2008 में राजशाही खत्म कर दी गई थी, और तब से नेपाल में पुरानी लिबरल नेपाली कांग्रेस के साथ माओवादी गुटों के अलग-अलग गठबंधन के ज़रिए पार्लियामेंट्री सरकार रही है। लेकिन, परिणाम क्या निकला? बार-बार सत्ता में आने का अवसर मिलने के बावजूद, कांग्रेस-कम्युनिस्ट जनता की उम्मीदों पर खरे नहीं उतर सके। बजाय इसके, उन्होंने बेरोज़गारी और भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया, अर्थव्यवस्था चौपट कर दी। इस बीच राजावादियों को लगा कि वो मौके पर चौका मार सकते हैं। लेकिन, इस आंधी में वो भी नहीं टिक पाए।

ओली का इस तरह से जाना, कहीं न कहीं चीनी कूटनीति की हार भी मानी जाएगी। ओली कुछेक महीने चुप रहे, मगर उनका पिछला ट्रैक रिकार्ड भारत विरोध वाला रहा है। कुछ वैसा ही रुख़ प्रचंड का रहा था। ये लोग जब-जब घरेलू मोर्चे पर विफल रहे, भारत विरोध का ब्रह्मास्त्र चला देते थे। चीन के बार-बार कहने के बावजूद, नेपाली वामपंथी एक होकर भी नहीं रहे। बाबूराम भट्टराई ने माओवादियों को छोड़कर एक 'नई शक्ति' बनाने की कोशिश की। लेकिन, वह भी ज़मीन पर नकार दिए गए। नेपाल में वामपंथ की राजनीति में टूट, विलय बहुतों बार हुआ है। तराई के नेता कब किसके संग सौदेबाज़ी कर लें, उनका कोई भरोसा नहीं था। तो, पब्लिक कब तक बर्दाश्त करती?

इस बार नेपाली संसद में युवा प्रतिनिधियों की संख्या 38 प्रतिशत हुई है। आप चाहें, इसे जेन-जी का कमाल समझें। 59 युवा सांसदों में से 51 आरएसपी के हैं। इस आयु वर्ग में नेपाली कांग्रेस के चार प्रतिनिधि हैं, जबकि सीपीएन-यूएमएल के दो प्रतिनिधि हैं। राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी के उम्मीदवार ने भी जीत हासिल की है। 2022 में निर्वाचित सांसदों में, सबसे बड़ा प्रतिनिधित्व 51-60 आयु वर्ग से आया था, जबकि केवल 11 प्रतिशत सदस्य 40 वर्ष से कम आयु के थे। इसी तरह, 2017 के चुनावों से चुने गए सदन में केवल 13 प्रतिशत सदस्य थे, जो 40 वर्ष से कम उम्र के थे।

पुष्परंजन

35 साल के बालेन शाह, सबसे कम उम्र के निर्वाचित प्रधानमंत्री होंगे। नेपाल पहली बार इस तरह का नज़ीर पेश कर रहा है। बालेन शाह भावनात्मक उबाल की उपज हैं। नेपाली समाज बालेन के बारे में बहुत कम जानता है। दिल्ली और पेइचिंग के लिए भी पहेली है बालेन शाह। युवाओं के बीच रैपर के रूप में चर्चित, काठमांडू के महापौर के रूप में बालेन शाह कितने सफल रहे? कोई वस्तुनिष्ठ अनुसंधान और विश्लेषण नहीं है। दूसरी ओर, उनके शुभचिंतक इस बात की सराहना नहीं करते कि उन्होंने काठमांडू का चेहरा बदल दिया। आलोचकों ने उन्हें एक 'भगोड़ा' कहा है, जो जिम्मेदारी से बचता है।

सेक्स रैकेट चलाने वाली दो बहनों के केस में नए खुलासे

भोपाल।

भोपाल के बागसेवनिया थाना क्षेत्र में सामने आए चर्चित धर्मांतरण और दुष्कर्म मामले में गिरफ्तार सगी बहनें अमरीन और आफरीन इस समय जेल में हैं। इस मामले में जांच के दौरान लगातार नए तथ्य सामने आ रहे हैं। पुलिस पूरे प्रकरण की अलग-अलग पहलुओं से जांच कर रही है ताकि पूरे घटनाक्रम की सच्चाई सामने आ सके।

जांच के दौरान यह भी पता चला है कि दोनों बहनों के परिवार का संबंध भोपाल के ईरानी डेरे से जुड़ा बताया जा रहा है। यह जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने इस दिशा में भी पड़ताल शुरू कर दी है। सूत्रों के अनुसार, जब दोनों बहनें अपने परिवार के साथ अब्बास नगर की झुग्गियों में रहती थीं, उसी दौरान उनके परिवार की ईरानी डेरे से नजदीकियां बढ़ी थीं। अब पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि वहां के आपराधिक छवि वाले लोगों से उनका कोई संपर्क था या नहीं।

ब्यूटी पार्लर की आड़ में सेक्स रैकेट

पुलिस जांच में यह बात भी सामने आई है कि दोनों बहनों ने ब्यूटी पार्लर की आड़ में अपना नेटवर्क तैयार किया था। अधिकारियों को शक है कि इसी माध्यम से कई युवतियों को जाल में फंसाया गया हो सकता है। इसलिए पुलिस यह भी पता लगाने में जुटी है कि अब तक कितनी लड़कियां इस पूरे मामले से प्रभावित हुई हैं।

एडिशनल डीसीपी गौतम सोलंकी के मुताबिक पुलिस इस मामले की हर दिशा से जांच कर रही है। उन्होंने कहा कि ईरानी डेरे से जुड़े पहलुओं की भी जांच की जा रही है, हालांकि अभी स्थिति पूरी तरह साफ नहीं है। पुलिस का कहना है कि जो भी तथ्य और सबूत सामने आएंगे, उनके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी और जांच जारी रहेगी।

परिवार में चार बहनें और दो भाई

अमरीन और आफरीन के परिवार में कुल चार बहनें और दो भाई हैं। इनमें से दो बहनों की शादी हो चुकी है, जबकि भाइयों में से एक मानसिक रूप से बीमार बताया जाता है। पुलिस जांच में यह भी सामने आया है कि बिलाल नाम का युवक, जो उनका मौसेरा भाई है, इस पूरे मामले में उनका सहयोगी माना जा रहा है। बिलाल मूल रूप से मुंबई का रहने वाला है, लेकिन वह भोपाल आकर अब्बास नगर स्थित घर में दोनों बहनों के साथ रहने लगा था। फिलहाल पुलिस को जानकारी मिली है कि वह मुंबई में मौजूद है। पीड़िताओं ने अपनी शिकायत में यह भी आरोप लगाया है कि अमरीन और आफरीन का गिरोह एमडी ड्रग्स की तस्करी से भी जुड़ा हुआ है।

चंदन यादव अमरीन और आफरीन के साथ रहता था

एफआईआर के अनुसार, चंदन यादव नाम का युवक सागर रॉयल विला में अमरीन और आफरीन के साथ रहता था। बताया गया है कि दोनों बहनों के संपर्क में आने के बाद उसने इस्लाम धर्म अपना लिया था। पीड़िताओं का कहना है कि अमरीन और आफरीन उन्हें गुजरात और मुंबई भी लेकर गई थीं, जहां उन्हें अनजान लोगों के साथ संबंध बनाने के लिए मजबूर किया गया। इतना ही नहीं, दोनों बहनें उन्हें शराब पीने और एमडी ड्रग्स लेने के लिए भी दबाव डालती थीं।

कई लड़कियों को देह व्यापार में धकेला

एफआईआर दर्ज कराने वाली दोनों पीड़िताओं का आरोप है कि आरोपी बहनें अब तक करीब पांच से सात लड़कियों को देह व्यापार में धकेल चुकी हैं। उनका तरीका भी लगभग एक जैसा होता था। सबसे पहले वे लड़कियों को बच्चे की देखभाल के नाम पर अपने घर में नौकरी पर रखती थीं। इसके बाद उन्हें अपने साथ घुमाने-फिराने ले जातीं और महंगी पार्टियों में भी शामिल कराती थीं। मौका मिलने पर चंदन, बिलाल और चानू उर्फ हाशिम रजा उनके साथ दुष्कर्म करते थे।

पीड़िताओं का कहना है कि जब लड़कियां विरोध करतीं या शिकायत की बात करतीं तो उन्हें बदनामी का डर दिखाकर चुप करा दिया जाता था। बाद में काम दिलाने के बहाने उन्हें अहमदाबाद भेज दिया जाता था, जहां यासिर नाम का व्यक्ति उन्हें स्पा सेंटर में नौकरी का झांसा देकर देह व्यापार के लिए मजबूर करता था।

ग्राम पंचायत के 18 फलियों के समाजजनों ने 'मीशन डी 3' को लेकर की बैठक

माही की गूंज, बरझर। फिरोज खान

ग्राम पंचायत बरझर के 18 फलियों के समाजजनों ने एकजुट होकर 'मिशन डी3' के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया। इस बैठक में समाज में व्याप्त कुरीतियों को दूर करने और फिजूलखर्ची पर लगाम लगाने के लिए कई कड़े और सुधारात्मक निर्णय लिए गए। सर्वसम्मति से तय किया गया कि अब शादियों, उजवन (नुक्ता) या घरों में अंग्रेजी शराब पिलाना, भाटी लाना और मांग कर शराब पीना पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। साथ ही, डीजे बजाने पर भी पूर्ण रोक लगा दी गई है, हालांकि शादी में सामान्य स्पीकर बजाने की अनुमति रहेगी।

बैठक में आर्थिक और सामाजिक नियमों को लेकर स्पष्ट रूप से निम्नलिखित बिंदु तय किए गए:-

दहेज (देज देजा): 2,25,000 रुपए निर्धारित।

लाग भागः 25,000 रुपए तय।

चांदी का मानः लड़की के पिता की ओर से 250 ग्राम और लड़के के पिता की ओर से 500 ग्राम।

नाबालिग मामलाः नाबालिग लड़का-लड़की के भाग जाने पर 1,51,000 रुपए का गुनाह (लेने और देने दोनों पर लागू)।

जबरन पकड़नाः किसी लड़की को जबरदस्ती पकड़ने पर 51,000 रुपए का दंड।

दूसरी शादीः एक पत्नी के रहते हुए दूसरी शादी करने पर 5,51,000 रुपए का दहेज लिया जाएगा।

भागजडाई शुल्कः लड़की पक्ष की ओर से 4,000 रुपए और लड़के पक्ष की ओर से 6,000 रुपए (कुल 10,000)।

अन्य रस्में: पुजाराना 2,000, हा-हो (नक्की ना) 2,000, धार ना 500 और तडवी ना 2,000 रुपए तय किए गए।

उक्त आयोजित इस बैठक में सरपंच, पटेल, तडवी, चौकीदार और सभी पंचों सहित जिम्मेदार नागरिकों ने हिस्सा लिया। जिनमें मुख्य रूप से सरपंच हिमसिंह बारिया , पुलिस चौकी प्रभारी शिवा तोमर , तेरसिंह तडवी, छगन तडवी, रतना तडवी, वैस्ता तडवी, झीतरा तडवी, भारता तडवी, चौकीदार दिनेश, हिमसिंह, ललित, वालचन्द, सोमला, पंच तेरसिंह, छगन, रतना, मासूम, चुनेसिंह, तेरसिंह भाई, रमण भाई, सेवला निनामा, करण भाई, काजु भाई, सतेसिंह भाई, समैश भाई, बापु भाई , मदन भाई, लसीया भाई, वैसता भाई, बलु भाई, नारू भाई, राजेश भाई, अमरसिंह भाई, चैना भाई, नरेश भाई, गोपाल भाई, ललित भाई, बरझर चौकी प्रभारी शिवा तोमर, सुधिर त्रिवेदी और पैसा एक्ट ब्लॉक कोऑर्डिनेटर सोनिया भाबर आदि उपस्थित रहे।

केंद्र से एमपी को मिला बड़ा तोहफा

भोपाल।

केंद्र से मध्य प्रदेश को बड़ी सौगात मिली है। उज्जैन अब सीधे दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे से जुड़ेगा। गुजरात और महाराष्ट्र के श्रद्धालु सिंहस्थ के दौरान दो घंटे में उज्जैन पहुंच जाएंगे। 2028 सिंहस्थ से पहले इस प्रोजेक्ट का काम पूरा हो जाएगा। बताया जा रहा है कि बेहद कम समय में इस प्रोजेक्ट को केंद्र से मंजूरी मिली है।

सीएम यादव ने जताया आभार

सीएम मोहन यादव ने एनएच-752डी के बदनावर-पेटलावद-थांदला-टिमरवानी सेक्शन को 3,839 करोड़ रुपए की लागत से फोर-लेन करने की मंजूरी देने के लिए केंद्रीय कैबिनेट का आभार जताया। उन्होंने कहा कि यह कॉरिडोर उज्जैन से दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे के टिमरवानी इंटरचेंज तक सीधी चार-लेन कनेक्टिविटी देगा।

आर्थिक विकास को मिलेगी गति

उन्होंने इसे एक अहम प्रोजेक्ट बताया जिससे इंदौर, पीथमपुर, उज्जैन और देवास के इंडस्ट्रियल सेंटर तक आसानी से पहुंचा जा सकेगा, साथ ही धार और झाबुआ जिलों का पूरा आर्थिक विकास भी पक्का होगा। मुख्यमंत्री यादव ने कहा कि यह मंजूरी और भी अहम हो जाती है क्योंकि इससे सिंहस्थ 2028 के दौरान श्रद्धालुओं का आना-जाना आसान हो जाएगा। इस फैसले के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय कैबिनेट का दिल से शुक्रिया।

2028 तक बढ़ा जल जीवन मिशन

सीएम मोहन यादव ने 'जल जीवन मिशन' का समय दिसंबर 2028 तक बढ़ाने और कुल लागत बढ़ाकर 8.69 लाख करोड़ रुपए करने के केंद्रीय कैबिनेट के फैसले का भी स्वागत किया, इससे 'हर घर को पानी' के संकल्प को नई तेजी मिलेगी।

केंद्रीय कैबिनेट ने दी है मंजूरी

पीएम मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमिटी ने मंगलवार को बदनावर-पेटलावद-थांदला-टिमरवानी सेक्शन से 80.45 किलोमीटर लंबे चार-लेन कॉरिडोर के डेवलपमेंट को मंजूरी दी। प्रस्तावित चार-लेन प्रोजेक्ट कॉरिडोर का मुख्य मकसद यात्रा की कुशलता में सुधार करना है और इससे यात्रा का समय लगभग एक घंटा कम होने की उम्मीद है। 70.40 किमी लंबे उज्जैन-बदनावर सेक्शन को पहले ही दो-लेन से चार-लेन में अपग्रेड किया जा चुका है।

गुजरात और महाराष्ट्र से दूरी हो जाएगी कम

टिमरवानी-थांदला-पेटलावद-बदनावर-उज्जैन कॉरिडोर गुजरात और महाराष्ट्र से उज्जैन के लिए ट्रैफिक का सबसे छोटा रास्ता है। वहीं, टिमरवानी-बदनावर सेक्शन के अपग्रेडेशन से इंटर-स्टेट कनेक्टिविटी मजबूत होगी और ट्रैफिक का कुशल मूवमेंट हो सकेगा। इस बेहतर लिंकेज से लॉजिस्टिक्स की लागत कम होगी, कच्चे माल और तैयार माल की कुशल आवाजाही आसान होगी और इंदौर, पीथमपुर, उज्जैन और देवास में मौजूद इंडस्ट्रियल हब/मल्टी-मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क तक पहुंच मजबूत होगी।

प्रस्तावित प्रोजेक्ट हाई स्पीड कनेक्टिविटी देता है जिसे बेहतर सुरक्षा और बिना रुकावट ट्रैफिक मूवमेंट के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिससे यात्रा का समय, भीड़भाड़ और ऑपरेटिंग लागत कम होगी।

18 थाना प्रभारियों की सुरक्षा में जेसीबी चलाकर जमींदोज किए मकान

माही की गूंज, धार।

जिले में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई कर विधायक की जमीन मुक्त करा ली। जमीन विवाद के बाद राजस्व और पुलिस की संयुक्त टीम ने सोमवार को अतिक्रमण हटा दिया। यहां जबर्दस्त सुरक्षा व्यवस्था के बीच अभियान चलाकर कई मकान जमींदोज कर दिए गए। धामनोद थाना क्षेत्र के सिरसोदिया गांव में बीजेपी विधायक कालूसिंह ठाकुर और पड़ोसियों के बीच जमीन पर कब्जे को लेकर विवाद था। तीन दिन पूर्व जब प्रशासनिक टीम अतिक्रमण हटाने के लिए आई तो ग्रामीणों ने पथराव कर दिया। इससे टीआई, महिला आरक्षक और चौकीदार घायल हो गए थे। हिंसा की इस गंभीर वारदात को ध्यान में रखते हुए आज करीब 300 पुलिसकर्मियों को मौके पर तैनात किया गया था। 18 थाना प्रभारियों की उपस्थिति में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई।

भारी पुलिस फोर्स के साथ वरिष्ठ राजस्व और पुलिस अधिकारियों ने सिसौदिया गांव में मोर्चा संभाल लिया था। गांव के सर्वे नंबर 77, 78, 79 और 80 की जमीन को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था जिसके निराकरण के लिए यहां ?काबिज अवैध निर्माण धराशायी कर दिए गए।

सिविल कोर्ट द्वारा अतिक्रमणकारियों का केस निरस्त कर दिए जाने के बाद तहसीलदार ने जमीन पर से अवैध कब्जा हटाने के आदेश दिए थे। 3 ?दिन पहले पुलिस-प्रशासन कार्रवाई करने पहुंचा जिसके दौरान ग्रामीणों ने पथराव कर दिया। इससे पुलिसकर्मी घायल हो गए थे।

समय दिया था

वारदात के बाद प्रशासन ने अतिक्रमणकारियों को अपने निर्माण हटाने के लिए 2 दिनों का समय दे दिया था। यह मियाद पूरी हो जाने के बाद प्रशासनिक टीम आज दोबारा गांव में पहुंची और अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरु की। अवैध कब्जे हटने के बाद भी गांव में शांति व्याप्त है।

दो दिवसीय कृषि मेला एवं प्रदर्शनी का आयोजन

माही की गूंज, आलीराजपुर।

कृषक कल्याण वर्ष 2026 के अवसर पर जिला आलीराजपुर में 11 और 12 मार्च को दो दिवसीय जिला स्तरीय कृषि मेले का आयोजन किया गया। यह आयोजन कृषि उपज मंडी समिति आलीराजपुर में किया आयोजित किया गया। जिला स्तरीय कृषि मेले विभागीय एवं निजी विक्रेताओं द्वारा प्रदर्शनी लगाई गई। जिनमें कृषि विज्ञान केंद्र आलीराजपुर, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, पशुपालन विभाग, जिला अग्रणी बैंक, जिला आयुष विभाग, महिला बाल विकास विभाग, उद्यानिकी विभाग, सहकारिता विभाग ,जिला परियोजना प्रबंधक आजीविका मिशन,सहित कृषि संबद्ध अन्य विभागों द्वारा मेले में विभागीय योजनाओं पर आधारित प्रदर्शनी लगाई गई। मेले में किसानों को आधुनिक कृषि तकनीकों, उन्नत बीजों, फसल विविधीकरण, मिलेट्स एवं तिलहन उत्पादन, कृषि यंत्रीकरण, प्राकृतिक एवं जैविक खेती, ई टोकन उर्वरक वितरण की जानकारी दी गई।

कलेक्टर की अध्यक्षता में वन एवं राजस्व विभाग की संयुक्त बैठक संपन्न

माही की गूंज, आलीराजपुर।

कलेक्टर श्रीमती नीतू माथुर की अध्यक्षता में बुधवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में वन विभाग एवं राजस्व विभाग की संयुक्त बैठक आयोजित की गई। बैठक में वन एवं राजस्व विभाग के संयुक्त सीमांकन, वन व्यपवर्तन प्रकरण, वन अधिकार पत्र, वन व्यवस्थापन की कार्यवाही, कट्ठीवाड़ा एवं मथवाड में ईको पर्यटन, लघु वनोपज महुआ अंतर्राज्यीय बैरियर, परिक्षेत्र कट्ठीवाड़ा में बाघ के विचरण, रेशम उद्योग तथा वन धन विकास केंद्र में प्रशिक्षण सहित विभिन्न विषयों पर विस्तृत चर्चा की गई और आवश्यक कार्यवाही के निर्देश दिए गए।

बैठक के दौरान कलेक्टर श्रीमती नीतू माथुर ने रेशम उद्योग को बढ़ावा देने के लिए आजीविका मिशन के अंतर्गत स्वयं सहायता समूहों को इसमें शामिल करने के निर्देश दिए, ताकि स्थानीय लोगों को रोजगार के अधिक अवसर मिल सकें। साथ ही जिले में ईको पर्यटन को बढ़ावा देने, ईको पर्यटन स्थलों पर नवाचार करते हुए उन्हें अधिक आकर्षक बनाने के लिए एक विस्तृत कार्ययोजना तैयार कर उसके प्रभावी क्रियान्वयन के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए। उन्होंने बैठक में उपस्थित सभी विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया कि शासन की योजनाओं को जमीनी स्तर तक पहुंचाने के लिए सभी विभाग आपसी समन्वय और सहयोग से कार्य करें तथा जनकल्याण को ध्यान में रखते हुए योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करें, ताकि आमजन को अधिकतम लाभ मिल सके। बैठक में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्रीमती संघमित्रा गौतम, डीएफओ अमित निकम, संयुक्त कलेक्टर एवं अनुविभागीय अधिकारी राजस्व मनोज गरवाल, सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग, कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग, महाप्रबंधक उद्योग विभाग, सहित वन विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे।

'मिस्टर जी' को भेजी आखिरी सेल्फी और मैसेज, बोली - 'मेरी शादी तुड़वा दी'

माही की गूंज, धार।

शहर की अर्जुन कॉलोनी में दोपहर बाद दर्दनाक घटना सामने आई, जहां 24 वर्षीय युवती ने प्रेम संबंध में धोखा मिलने से आहत होकर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना दोपहर करीब 12 से 1 बजे के बीच की बताई जा रही है। मृतका शारदा पिता जोगडिया शेरवाल घर के कमरे में अकेली थी, जबकि उसकी भाभी बाहर काम कर रही थीं। घर में भाई के छोटे बच्चे भी मौजूद थे। इसी दौरान बच्चे के रोने की आवाज सुनकर भाभी कमरे में पहुंची तो शारदा फांसी के फंदे पर लटकी मिली।

परिजनों ने तुरंत उसे नीचे उतारकर अस्पताल पहुंचाया, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी। शाम को पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। पुलिस ने सुसाइड नोट, मोबाइल चैट और अन्य साक्ष्य जब्त कर लिए हैं। मामले में युवक की भूमिका की भी जांच की जा रही है।

चार साल से था प्रेम संबंध

परिजनों के अनुसार युवती पाटीदार चौराहा स्थित एक निजी क्लीनिक में काम करती थी, जहां महेश प्रजापत नाम का युवक भी कार्यरत था। दोनों के बीच करीब चार साल से प्रेम संबंध थे। बताया जा रहा है कि युवती के परिवार ने उसकी शादी कहीं और तय कर दी थी। यह बात उसने महेश को बताई थी। आरोप है कि महेश ने शादी का भरोसा दिलाते हुए युवती से कहा कि वह परिवार को मना कर दे और दो-तीन साल बाद वह उससे शादी करेगा। बाद में युवक अपने वादे से मुकर गया, जिससे युवती गहरे तनाव में आ गई।

फांसी लगाने से पहले भेजी सेल्फी

घटना से पहले युवती ने गले में फंदा डालकर अपनी एक सेल्फी ली और प्रेमी को भेज दी। इसके साथ उसने एक भावुक संदेश भी लिखा, जिसमें अपने दर्द और टूटे भरोसे का जिक्र किया। युवती ने अपने मोबाइल में युवक का नंबर मिस्टर जी नाम से सेव कर रखा था। परिजनों को मोबाइल में दोनों के बीच हुई कई चैट भी मिली हैं, जिन्हें पुलिस को सौंप दिया गया है। पुलिस को मौके से दो पेज का सुसाइड नोट भी मिला है, जिसमें युवती ने अपनी पीड़ा व्यक्त की है।

जांच कर रहे हैं

अर्जुन कॉलोनी में युवती द्वारा फांसी लगाकर आत्महत्या करने का मामला सामने आया है। शव का पंचनामा बनाकर पोस्टमार्टम कराया गया है। सुसाइड नोट, मोबाइल चैटिंग सहित अन्य साक्ष्य संकलित किए गए हैं। इनके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। - **दीपक सिंह चौहान, थाना प्रभारी कोतवाली धार**

राजू की पत्नी व 7 वर्ष की पुत्री माया की मां को कुंवारी बताकर देवीगढ़ में की शादी

मामले में बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ का स्लोगन भी हो रहा फेल...

माही की गूंज, खवासा।

झाबुआ जिले में भांजगडी प्रथा इस कदर चरम पर है कि, यह भांजगडीए अपने क्षणिक लाभ के लिए सही को गलत और गलत को सही और दिन को रात और रात को दिन बता देते है। तथा ऐसे में यह भांजगडीए शादीशुदा महिला को कुंवारी बताकर अन्य जगह शादी करवाने में भी पीछे नहीं रहे हैं।

ऐसे ही एक मामले में मायके पक्ष व भांजगडीओं की एक बड़ी करतूत सामने आई है। जिसमें हमारा आदिवासी समाज भी शर्मशार होता नजर आ रहा है। जिले में एक शादीशुदा महिला अन्य के साथ भाग कर रहती व शादी कर लेती है ,तथा नाबालिक बच्चे तक भाग कर अपना जीवन साथी चुनने का प्रयास करते हैं यह आम बात हो चुकी है। पर किसी शादीशुदा महिला को वह भी बच्चों की मां हो और उस विवाहित महिला को पति के होते हुए बिना किसी खुलासे (तलाक) के कुंवारी बताकर अन्य जगह शादी कर देने का मामला शायद ही कोई सामने आते होंगे मगर यह मामला हुआ है।

मामला यह कि, खवासा (थांदला) चौकी अंतर्गत ग्राम रतनाली निवासी राजू पिता टीटा भूरिया की शादी लगभग 9-10 वर्ष पूर्व बामनिया (पेटलावद)चौकी क्षेत्र के ग्राम मोई चारणी निवासी ताहजिंग गामड़ की पुत्री अनीता गामड़ से हुई थी। इनका वैवाहिक जीवन चार पांच वर्ष तक निर्विवादित व सही रहा। राजू व अनीता की एक पुत्री ने भी जन्म लिया जिसकी अब लगभग 7 वर्ष उम्र है।

राजू भूरिया ने बताया कि, चार पांच वर्ष तक हम पति-पत्नी के बीच किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं हुआ था। जिसके बाद छोटी-बड़ी घरेलू बातों पर पति-पत्नी के बीच कुछ कहा सुनी होती। तो मामूली बात को बड़ा विवाद का रूप मेरा काका उर्फ मेरी पत्नी अनीता का जीजा मुन्ना उर्फ मोहन तुल देता और आग में घी डालकर विवाद को बढ़ावा देता। ऐसे में पूर्व में खवासा और बामनिया चौकी में हम पति-पत्नी के रिपोर्ट आवेदन भी प्रस्तुत किए गए थे व समझौते भी पंचों के बीच हुए थे। जिसके बाद पत्नी का आना-जाना पीयर व मेरे पास रहा। लेकिन पिछले दो-तीन वर्ष पूर्व मेरी पत्नी ने मुझसे पीयर जाने की बात कही, जिस पर मैं, मेरी पत्नी अनीता व मेरी बेटी माया के साथ उसके मायके में रहने हेतु राजी-खुशी छोड़कर आया। कुछ दिन बाद जब मैं, मेरी पत्नी व बेटी को लेने गया तो मेरा साला नारसिंह पिता ताहजिंग गामड़, छगन गामड़ व मोहन ऊर्फ मुन्ना भूरिया ने मेरे साथ विवाद किया और मेरी पत्नी वह बेटी को नहीं भेजा। वही विवाद के दौरान मुन्ना ऊर्फ मोहन ने कहा कि, अनीता मेरी साली है और मैं, मेरी जमीन बेचकर खुलासा कर मेरी औरत बनाऊंगा।

राजू भूरिया ने जानकारी देते हुए बताया कि, मैं, मेरे परिवार के साथ कई बार मेरे ससुराल मोई चारणी मेरी पत्नी व बेटी को लेने गया तो, कभी बताया घर पर नहीं है, तो कभी मजदूरी पर जाना बताया। लेकिन अभी पता चला है कि, मेरी पत्नी मजदूरी पर नहीं, कहीं और दे दी गई है, कहां दी यह पुरी तरह से नहीं पता है। इस संबंध में 9 व 10 मार्च को थांदला व पेटलावद थाने में लिखित रिपोर्ट भी दर्ज की हैं।

वही राजू ने बताया कि, हमारे रिश्तेदारों के माध्यम से 6 मार्च के पहले पता चला कि, मेघनगर ब्लॉक के ग्राम देविगढ़ के किसी दिनेश सिंगाड़ के साथ मेरी पत्नी अनीता को कुंवारी बताकर शादी कर दी गई। इस संबंध में जब देविगढ़ सरपंच राजेश मकना जाति बामनिया से बात हुई तो बताया, मोई चारणी के पूर्व सरपंच छगन गामड़ व कोदली के पूर्व सरपंच विनेश कटारा ने देवीगढ़ निवासी दिनेश को बताया कि, अनीता कि सगाई ग्राम में हुई थी और वह अन्य लड़की को लेकर भाग गया है। अनीता कुंवारी लड़की है और यह दोनों भांजगडीए 55 हजार रूपए भी यहां से ले गए थे।

राजु भूरिया रतनाली।

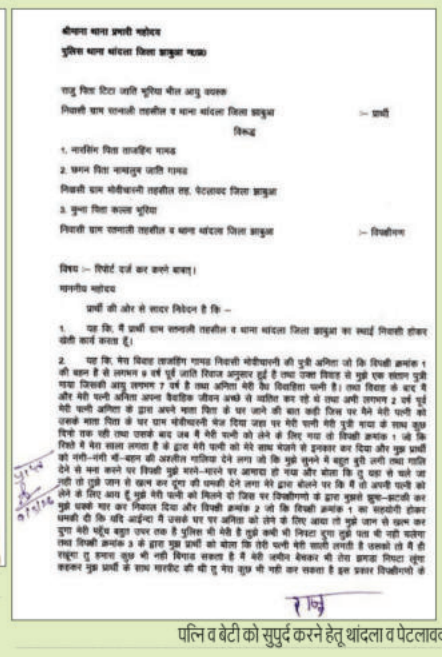

पत्नि व बेटी को सुपुर्द करने हेतू थांदला व पेटलावद थाने में राजु भूरिया ने लिखित में की रिर्पोट दर्ज।

जब माही की गूंज प्रतिनिधि की बात देविगढ़ सरपंच राजेश बामनिया से हुई तो बताया, भांजगडीए एवं लड़की के मायके पक्ष ने शादीशुदा को कुंवारी बताया और एक घर को तोड़ दूसरे घर को बसाने का प्रयास झूठ बोलकर किया यह गलत है। इन सारे मामले में उस मासूम बच्ची का क्या भविष्य होगा, वह किसको अपना पिता कहेगी? इस मामले का फैसला होना चाहिए।

वही इस पुरे मामले मे बताया जा रहा है कि, 7 वर्षिय राजु की बेटी माया मामा के पास ही है पर 7 वर्ष बाद भी मासुम माया को शिक्षा हैतु स्कूल नही भेजा गया है। ऐसे में इस मामले में माया का भविष्य भी अधर में दिखाई दे रहा है। तथा सरकार का बेटी बचाओं-बेटी पढ़ाओं का स्लोगन भी फेल होता दिखाई दे रहा है।

बिजली आपूर्ति बाधित, जल जीवन मिशन भी फेल, गहराया जलसंकट

माही की गूंज ,पेटलावद।

पेटलावद क्षेत्र की ग्राम पंचायत झोसर में इन दिनों भीषण गर्मी के बीच ग्रामीण बूंद-बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। करीब 35 सौ की आबादी वाली इस पंचायत में जल जीवन मिशन के तहत बनी पेयजल टंकी सफेद हाथी साबित हो रही है। महीनों से यह ढांचा खड़ा तो है, लेकिन आज तक इससे ग्रामीणों को एक बूंद पानी नसीब नहीं हुआ। विकास के इन कागजी दावों के बीच अब बिजली विभाग की कार्रवाई ने ग्रामीणों के जख्मों पर नमक छिड़कने का काम किया है। विद्युत मंडल ने मैंड़ा फलिया और डाबरिया फलिया की बिजली काट दी है, जिससे पेयजल का संकट गहरा गया है। आलम यह है कि, तपती धूप में बुजुर्ग, महिलाएं और छोटे बच्चे सिर पर बर्तन रखकर मीलों भटकने को मजबूर हैं। कहीं सूखे हेडपंप तो कहीं गहरे कुओं में जान जोखिम में डालकर ग्रामीण पानी निकाल रहे हैं।

वर्तमान समस्या के पीछे बिजली विभाग के आउटसोर्स कर्मचारियों की बड़ी लापरवाही सामने आ रही है। ग्रामीण विजय कटारा ने आरोप लगाया कि, विभाग के कर्मचारी, ग्रामीणों से बिल की राशि तो वसूल लेते हैं, लेकिन उसे दफ्तर में जमा नहीं करते। अब जब शादियों का सीजन और गर्मी शुरू हुई है, तो विभाग ने बकाया बताकर कनेक्शन काट दिए हैं। स्थिति इतनी विकट है कि शादियों के लिए ग्रामीणों को भारी खर्च कर जनरेटर किराए पर लाने पड़ रहे हैं।

महिला रेखा भूरिया का कहना है कि, चार दिनों से बिजली गुल होने के कारण घर का पूरा कामकाज ठप हो गया है और घरेलू पशुओं के लिए पानी का इंतजाम करना नामुमकिन होता जा रहा है। ग्रामीण दावा कर रहे हैं कि, वे सवा सौ रुपए महीने का नियमित बिल देने को तैयार हैं, लेकिन कर्मचारियों के गलत व्यवहार और पैसों के गबन ने उन्हें इस मुसीबत में डाल दिया है। इस कटौती का असर निनामा फलिया और पारगी फलिया पर भी पड़ा है, क्योंकि यहाँ की जलापूर्ति डाबरिया फलिए के ट्रांसफार्मर से जुड़ी है।

सरपंच प्रतिनिधि शैतान भूरिया ने बताया कि, जब इस संबंध में अधिकारियों और लाइनमैन से बात की गई, तो उन्होंने संतोषजनक जवाब देने के बजाय बातों को गोल-मोल घुमाया। वर्तमान में ग्रामीण निजी कुओं के भरोसे दिन काट रहे हैं, जबकि पशुओं की प्यास बुझाने के लिए मुख्य सड़क पर बने होद को नहर से पाइप बिछाकर किसी तरह भरा गया है।

उधर विद्युत वितरण कंपनी के जूनियर इंजीनियर हेमंत बामनिया का कहना है कि, क्षेत्र पर करीब सवा लाख रुपए का बकाया है, जिसके कारण यह कार्रवाई की गई है। उन्होंने यह भी कहा कि यदि किसी कर्मचारी ने पैसे लेकर जमा नहीं किए हैं, तो ग्रामीण प्रमाण के साथ आकर बात करें। फिलहाल मार्च का महीना होने के कारण वसूली का दबाव है, लेकिन बातचीत के जरिए समाधान निकाल कर बिजली बहाल की जा सकती है।

नल जल योजना : पाइप लाईन डालते ही टेसि्टंग में ही फूटे पाइप

माही की गूंज, खवासा।

नल जल योजना में हो रहे कार्यों की अनियमित्ताए व करोडो़ के भ्रष्टाचार के खुलासे हो चुके हैं। बावजूद उक्त योजना के अंतर्गत हो रहे कार्य में कोई सुधार नहीं देखा जा सकता है। ग्राम खवासा में भी नल जल योजना के तहत कृषि मंडी परिसर के आगे सड़क किनारे ही बिना किसी गाइड लाईन के टंकी का निर्माण किया जा रहा है। जबकि इसी बामनिया मार्ग पर टंकी बनी हुई है लेकिन पूर्व में बनी टंकी सड़क मार्ग से थोड़ी अंदर है। नई बन रही पानी की टंकी के नीचे अगर कोई समवेल बनाना हो या फिर फिल्टर प्लांट बनाना हो तो वह उक्त टंकी के नीचे बनाना असंभव ही होगा। वही खवासा में जल स्त्रोत की कमी है तथा नई उक्त पेयजल योजना के तहत हो रहे कार्य में भी जल स्त्रोत का कोई स्थाई हल नहीं निकाला गया है। 10 वर्ष पूर्व भी पीएचई विभाग ने ढ़ोलखरा के एरिकेशन तालाब के किनारे कुप का खनन बिना परमिशन से कर पानी खवासा में लाने का प्रयास किया था। लेकिन 50 लाख की उक्त योजना के तहत 50 घंटे पानी भी उक्त ढ़ोलखरा कूप से खवासा नहीं ला सकी।

इसी तरह 10 वर्ष बाद फिर ग्राम में पाइप लाईन नल जल योजना के तहत डाली जा रही है जिसमें भी गुणवत्ता का अभाव देखा जा सकता है। वही ग्राम की सीसी सड़क पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है। डाली जा रही पाइप लाईन 1 मीटर के ऊपर ही डाली जा रही है। तथा सामने आया कि, पाटीदार मोहल्ले में डाले गए नए पाइप की टेसि्टंग कर मोटर से सीधा पानी सप्लाई किया। मोटर से सीधा सप्लाई हुआ पानी के तहत ही निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर सवाल उठे और पाइप फूट गए। ऐसे में अगर टंकी से पानी सप्लाई होगा तो उसका प्रेशर अधिक होगा, ऐसे में यह पाइप लाईन आगे कितने समय सही सलामत चलेगी यह तो भगवान भरोसे ही है, यह ग्राम वासियों का कहना है। वही पाइप फूटने के साथ ही ग्राम में उक्त नल जल योजना के तहत अनियमित्ता व गुणवत्ता पर सवाल उठने लगे हैं। तो दूसरी और उक्त नल जल योजना के तहत ही खवासा में जल स्त्रोत हेतु उसी ढोलखरा एरिकेशन तालाब के किनारे नया कुप का खनन किया जाएगा कहा जा रहा है। लेकिन एरिकेशन विभाग से इस संबंध में कोई विधिवत्त कूप खनन की परमिशन अभी तक नहीं ली गई है। तथा फिल्टर प्लांट का भी कोई प्रोजेक्ट अभी तक नहीं बना है। यानी कि, आगे भी खवासा वासियों को 15 दिन से एक माह तक ही नलों से गर्मी में पानी मिलेगा कि संभावनाएं जताइ जा रही है।

ग्राम में मजबूत एवं स्थाई कार्य नल जल योजना के तहत हो, और ग्राम में वाल्व तीन से चार हो, तथा लाड़की, माही डेम या नर्मदा का जब तक खवासा वासियों के लिए पीने हेतु पानी का स्त्रोत तय नहीं किया जाता, तब तक खवासा वासियों को पीने के पानी का दंश झेलना ही पड़ेगा।

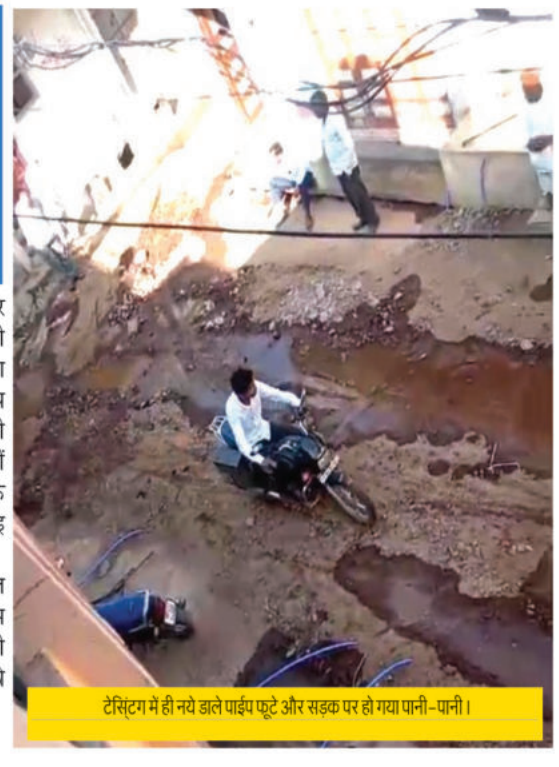

टेसि्टंग में ही नये डाले पाईप फूटे और सड़क पर हो गया पानी-पानी।

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक, अलका भटेवरा द्वारा काम्पेक प्रिन्टर्स प्रायवेट लिमिटेड, 3/54, प्रेस कॉम्प्लेक्स, ए. बी. रोड, इंदौर से मुद्रित एवं 499, बाजना मार्ग, गणेश मंदिर के सामने, खवासा, तहसील थांदला, जिला-झाबुआ (म.प्र.) से प्रकाशित। प्रधान संपादक- संजय भटेवरा। मोबाइल नं. -95898-82798 (सभी विवादों का न्यायालय क्षेत्र झाबुआ रहेगा) आरएनआई नंबर- एमपीएचआईएन/2018/76422